

वनानि दहतो वहेः सखा भवति मारुतः।
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यस्ति सौहृदम्॥

एक छोटे से दीप को बुझा देने वाली हवा भी दावानल की दोस्त बन जाती है।
शक्तिशाली का सभी समर्थन करते हैं।
- सुभाशिता

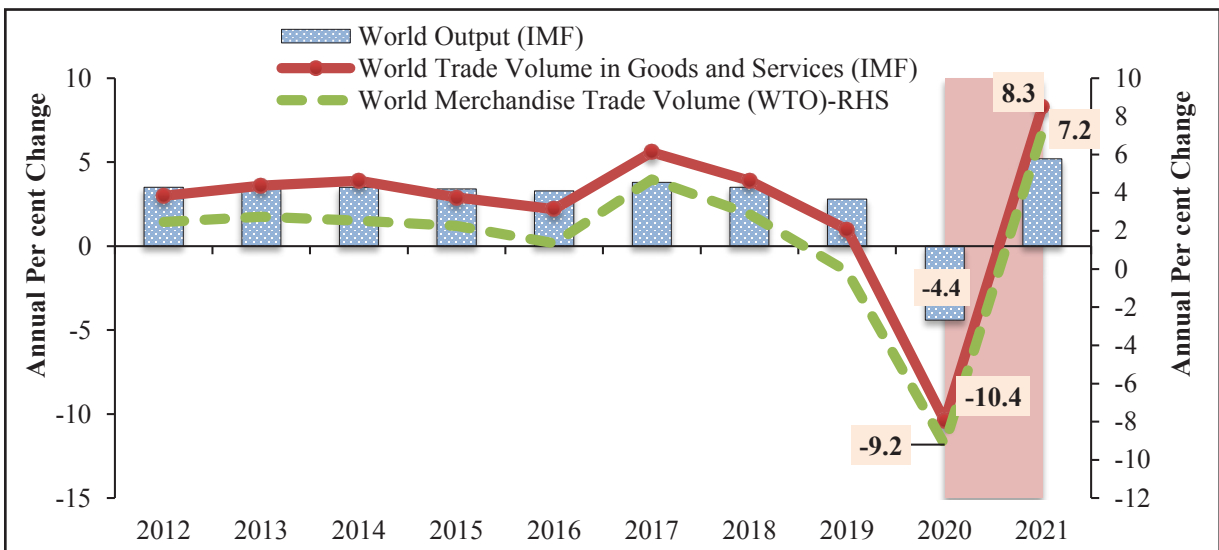
कोविड-19 महामारी ने 2020 महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन) के बाद से सबसे बुरी वैश्विक मंदी को जन्म दिया है; हालांकि, शुरू में जिस प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव की आशंका थी उसकी तुलना में कम नुकसान होने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई है, वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं और संकुचित बाहरी वित्तपोषण की स्थिति में चालू खाता शेष और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर अलग-अलग दुष्प्रभाव पड़े हैं। वैश्विक व्यापारिक व्यवसाय 2020 में 9.2 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है। कम आयात की वजह से चीन और अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। भारत के वैश्विक व्यापार की बदलती प्रकृति रत्न और गहने, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कमी और दवाओं और फार्मा, सॉफ्टवेयर और कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में सुधार के रूप में प्रकट हुई है। विशेष रूप से, फार्मा निर्यात ने इस अवसर का उपयोग भारत के कुल निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किया और भारत को दुनिया की फार्मेसी होने की संभावना को इंगित किया। समायोज्य (रिज़िलिएंट) सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातों के समर्थन से भारत को चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू खाते में 17 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से अधिशेष देखने की उम्मीद है। दूसरी ओर, पूंजी खाता शेष, मजबूत एफडीआई और एफपीआई प्रवाह से मजबूत हुआ है। इन परिवर्तनों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, जो 08 जनवरी, 2021 तक 586.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के उच्च स्तर तक पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई का हस्तक्षेप अस्थिरता और रुपये के एकतरफा अधिमूल्यन को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा है। हालांकि इस हेडलाइन मुद्रास्फीति के उच्च स्तर ने आरबीआई के समक्ष शास्त्रीय ट्राइलेमा (त्रिधापाश) की स्थिति उत्पन्न की है, जिससे एक ओर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाली संकुचित मौद्रिक नीति एवं वृद्धि के प्रोत्साहन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखा जा सके। इस पृष्ठभूमि से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए जिसमें शामिल हैं-उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी), व्यापार लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रयास निर्यात को सुगम बनाने में अधिक सहायक होंगे।

3.1 कोविड-19 ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की बढ़ती परस्परता द्वारा उत्प्रेरित प्रसार के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। परिणामी संकट ने वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट, कमोडिटी/माल की कीमतों में गिरावट, बाहरी वित्तपोषण की खराब स्थिति और चालू खाता शेष और मुद्राओं के लिए अलग-अलग प्रभाव के साथ एक तीव्र आघात किया है। 2020 के पहले पांच महीनों में माल व्यापार (गुड्स ट्रेड) की वैश्विक मात्रा 2019 की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम थी - जो वैश्विक संकट के पहले पांच महीनों में अप्रत्याशित अधिक संकुचन वाली स्थिति रही।

वैश्विक आर्थिक परिवेश

3.2 महामारी के प्रसार के कारण आर्थिक गतिविधियों से जुड़े निलंबन, आपूर्ति, श्रृंखला में व्यवधान, यात्रा प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कीमतों में अस्थिरता पैदा हुई। नतीजतन, वैश्विक उत्पादन वृद्धि और व्यापार की मात्रा में गिरावट की लहर थी। व्यापार में गिरावट की तुलना में जीडीपी में संकुचन वर्तमान मंदी में बहुत अधिक मजबूत हुआ है जो अधिक मध्यम रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अप्रैल 2020 में, विश्व व्यापार के व्यवसाय में 2020 में 13-32 प्रतिशत की गिरावट की भविष्यवाणी की। हालांकि, लॉकडाउन में ढील/छूट दिए जाने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी को कम करने के साथ, जून और जुलाई के महीनों में व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई। तदनुसार, डब्ल्यूटीओ ने अक्टूबर 2020 में अपने अनुमानों को संशोधित किया है जिसके अनुसार 2020 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 9.2 प्रतिशत की गिरावट आई है, इसके बाद 2021 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है (चित्र 1)। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अक्टूबर 2020 संस्करण में, आईएमएफ ने 2020 में विश्व उत्पादन में 4.4 प्रतिशत की तेज गिरावट की उम्मीद की थी, लेकिन 2020 के विश्व व्यापार की मात्रा में अप्रैल 2020 में की गई भविष्यवाणी अर्थात क्रमशः 3.0% तथा 11.0% (चित्र 1) की तुलना में 10.4 प्रतिशत संकुचन दर्ज किया गया था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जीडीपी के साथ-साथ व्यापार की मात्रा के संकुचन को उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की तुलना में अधिक गंभीर संकुचन होने का अनुमान है।

चित्र 1 : वर्ल्ड आउटपुट और ट्रेड वॉल्यूम की वृद्धि में रुझान



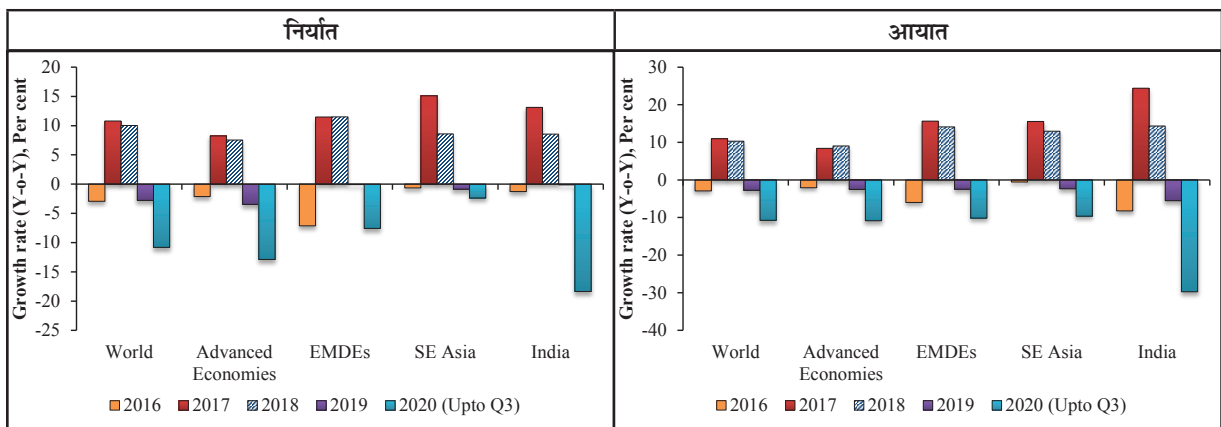
स्रोत : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन

नोट : 2020 और 2021 के आंकड़े अनुमानित हिस्से के रूप में दर्शाए गए हैं।

3.3 विश्व व्यापार संगठन से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वैश्विक व्यापार में, वैश्विक स्तर पर 2020 की दूसरी तिमाही में अब तक सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उक्त तिमाही के लिए डब्ल्यूटीओ का माल व्यापार बैरोमीटर सूचकांक 84.5-2007 के बाद से अब तक रिकॉर्ड पर सबसे कम था यानि, सूचकांक के लिए बेसलाइन वैल्यू 100 के 15.5 अंक के नीचे और पिछले साल की समान अवधि से 18.6 अंक नीचे है।

3.4 हालांकि, व्यापार पर प्रभाव क्षेत्रों में काफी भिन्नता है। 2020 में (क्यू 3 तक), आईएस को निर्यात में 12.9 प्रतिशत और आयात में 10.8 प्रतिशत की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जबकि ईएमडीई ने निर्यात में कम संकुचन 7.6 प्रतिशत और आयात में 10.1 प्रतिशत की कमी देखी। ईएमडीई के बीच, दक्षिण पूर्व एशियाई निर्यात उन्मुख देशों में अभी भी निर्यात में 2.4 प्रतिशत की कमी और आयात में 9.6 प्रतिशत की कमी देखी गई है।

चित्र 2 : वर्ल्ड मर्चेन्डाइज ट्रेड में रुझान : विकास दर (वाई-ऑन-वाई/वर्ष दर वर्ष)



स्रोत: विश्व व्यापार संगठन

3.5 विभिन्न प्रकार के सामानों में व्यापार पर प्रभाव भी काफी भिन्न होता है। जबकि कृषि उत्पादों का व्यापार दूसरी तिमाही (-5 प्रतिशत बनाम -21 प्रतिशत) में दुनिया के औसत से कम हो गया, यह ईंधन और खनन उत्पादों के मामलों में तेजी से गिर गया (38 प्रतिशत) क्योंकि कीमतें गिर गईं। इसके अलावा, मोटर वाहन उत्पादों के व्यापार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, हालांकि, दूरसंचार उपकरण (जिसमें स्मार्टफोन भी शामिल हैं), इलेक्ट्रॉनिक्स (घर से काम करने की सुविधा के लिए) और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में व्यापार की वृद्धि हुई।

3.6 आईएमएफ की अक्टूबर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 के अनुसार, अर्थव्यवस्था के लिए ऋण के प्रवाह को बनाए रखने और प्रतिकूल मैक्रो-फाइनेंशियल फीडबैक लूप से बचने के लिए अभूतपूर्व और समय पर नीतिगत प्रतिक्रियाओं के कारण निकटवर्ती वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिम अभी के लिए निहित हैं, जिसमें सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में कमजोरियां बढ़ी हैं, क्योंकि फर्मों ने नकदी की कमी और संप्रभु क्षेत्र में सामना करने के लिए अधिक कर्ज लिया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए राजकोषीय घाटे ने विस्तार किया है। ईएमडीई मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा आय के लिए उत्पाद निर्यात, परदेसी वित्तपोषण और पर्यटन पर निर्भर करते हैं, जिसमें महामारी की से काफी कमी आई है। हालांकि,

1 डब्ल्यूटीओ का माल व्यापार बैरोमीटर इंडेक्स का एक प्रमुख संकेतक है जो विश्व व्यापार वृद्धि के व्यापार की मात्रा के आंकड़ों से दो से तीन महीने पहले विश्व व्यापार विकास में व्यापार विकास में परिवर्तन का संकेत देता है। इसका आधारभूत मूल्य 100 है, 100 से अधिक का मान ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति की वृद्धि को दर्शाता है जबकि 100 के नीचे का मान अधोमुखी प्रवृत्ति के विकास को इंगित करता है।

अभी तक ईएमडीई पर इसका प्रभाव छह देशों-अरजेंटीना, इक्वाडोर, बेलीज, लेबनान, सूरीनाम और जाम्बिया-की अपेक्षा कम रहा है जिन्होंने अपने सॉवरेन ऋण पर चूक की है और केवल पहले दो ने अपने ऋणों का पुनर्गठन किया है। 2021 में संभावित ऋण चूक हो सकती है क्योंकि उस वर्ष चुकोती के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी ऋण का अनुमान है। भविष्य के मार्ग की कमियों को नीतिगत समर्थन की सीमा और पुनर्प्राप्ति (वसूली) की गति से तय किया जाएगा, जो कि अलग-अलग क्षेत्रों और देशों में असमान होने की उम्मीद है।

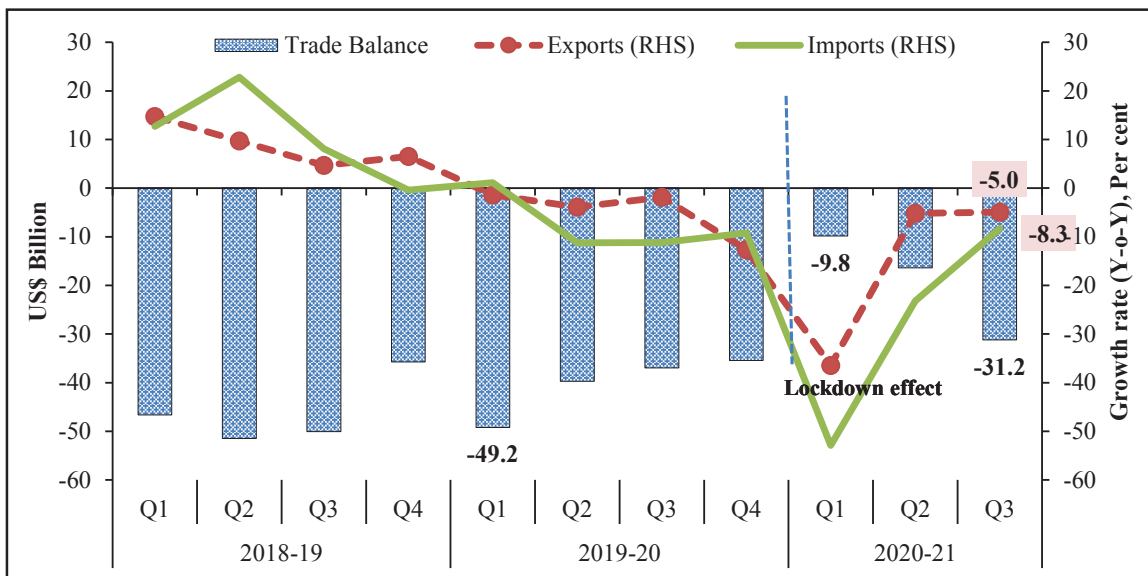
3.7 संक्षेप में कहा जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी अभूतपूर्व कोविड-19 के आघात के प्रभाव में ही है। इस अनिश्चित और अस्थिर वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच, भारत का वैदेशिक क्षेत्र तन्यता के लिए एक प्रमुख प्रशामक के रूप में उभरा है। भारत की आश्वासक वैदेशिक संतुलन स्थिति को लगातार तीन तिमाहियों में अधिशेष चालू खाता शेष, पोर्टफोलियो कैपिटल इनफ्लो की फिर से शुरुआत, मजबूत एफओआई इनफ्लो और विदेशी मुद्रा रिजर्व के निरंतर निर्माण द्वारा समर्थित किया गया है।

भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) में विकास की संभावनाएं

(मर्चेडाइज ट्रेड) व्यापारिक माल का व्यापार

3.8 वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान, भारत के निर्यात और आयात में वैश्विक व्यापार में संकुचन के अनुरूप ही तीव्र संकुचन देखा गया। आयात में गिरावट से निर्यात में कमी आई है-जिसके कारण पिछले साल की पहली तिमाही के दौरान यूएस \$ 49.2 बिलियन की तुलना में \$ 9.8 बिलियन के छोटे व्यापार घाटे के रूप में भारत ने 18 वर्षों के अंतराल के बाद जून, 2020 के महीने में व्यापार अधिशेष दर्ज किया। जून से अर्थव्यवस्था के अनलॉक होने के साथ, भारत के मर्चेडाइज व्यापार में एक क्रमिक पुनरुद्धार हुआ (चित्र 3) । अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 125.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में मात्र 57.5 बिलियन अमरिकी डालर था।

चित्र 3 : मर्चेडाइज ट्रेड बेलेंस (व्यापारिक माल व्यवसाय संतुलन), निर्यात और आयात की वृद्धि दर



स्रोत : वाणिज्य विभाग

3.9 प्रमुख वस्तुओं का विवरण जिसमें भारत में 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) की तुलना में 2020-21 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहा जो क्रमशः तालिका 1 और तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका-1: उत्पाद जिनमें भारत का मर्चेन्डाइज्ड व्यापार संतुलन अनुकूल है।

(यूएस \$ बिलियन में मूल्य)

क्रम सं.	उत्पाद	निर्यात		आयात		व्यापार संतुलन	
		अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर
		2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)	2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)	2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)
1	औषधि फॉर्मूलेशन, जैविक	10.6	12.4	1.5	1.7	9.0	10.7
2	समुद्री उत्पाद	4.8	4.0	0.1	0.1	4.7	3.8
3	सोना तथा अन्य कीमती धातु से बने आभूषण	9.6	4.0	0.5	0.2	9.1	3.8
4	आरएमजी कॉटन और ऐस्सेसरी	5.6	3.9	0.4	0.2	5.2	3.7
5	सूती कपड़े और परिधान	4.0	3.5	0.4	0.2	3.6	3.3
6	लोहा एवं इस्पात	6.4	7.7	8.0	4.7	-1.6	3.0
7	लौह अयस्क	1.7	2.8	0.1	0.1	1.6	2.7
8	बासमती चावल	2.5	2.7	0.0	0.0	2.5	2.7
9	(बासमती के अलावा) चावल	1.3	2.6	0.0	0.0	1.3	2.6
10	पेट्रोलियम उत्पाद	28.5	15.4	18.0	13.1	10.6	2.3

स्रोत: डीओसी

नोट: आर: संशोधित, पी: अनंतिम

तालिका-2: उत्पाद जिनमें भारत का मर्चेन्डाइज्ड व्यापार प्रतिकूल है।

(यूएस \$ बिलियन में मूल्य)

क्रम सं.	उत्पाद	निर्यात		आयात		व्यापार संतुलन	
		अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर
		2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)	2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)	2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)
1	कच्चा तेल	0.0	0.0	68.0	31.2	-68.0	-31.2
2	सोना	1.2	0.6	20.6	12.3	-19.4	-11.7
3	कोयला, कोक और ब्रिक्केट्स आदि	0.1	0.0	15.6	9.7	-15.5	-9.7
4	टेलीकॉम उपकरण	3.1	2.2	10.3	9.8	-7.2	-7.6
5	इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे	1.7	1.5	11.7	8.7	-10.0	-7.2
6	वनस्पति तेल	0.1	0.3	6.4	6.8	-6.3	-6.5
7	कम्प्यूटर हार्डवेयर और सहायक उपकरण	0.2	0.2	6.5	6.6	-6.3	-6.4
8	निर्मित उर्वरक	0.1	0.1	5.0	5.5	-5.0	-5.4
9	कच्चा प्लास्टिक पदार्थ	2.4	2.3	7.2	5.2	-4.8	-2.9
10	एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और पुर्जे	0.9	0.8	7.0	3.6	-6.0	-2.8

स्रोत: डीओसी

नोट: आर: संशोधित, पी: अनंतिम

3.10 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) की तुलना में 2020-21 (अप्रैल-नवंबर) की अवधि के लिए प्रमुख देशों के लिए भारत का व्यापारिक व्यवसाय संतुलन तालिका 3 में यह दर्शाता है कि भारत का यू एस ए के साथ-साथ बांग्लादेश और नेपाल से अधिक अनुकूल व्यापार संतुलन है। अप्रैल, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर, 2019-20 के दौरान सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन के बाद ईराक और सऊदी अरब के साथ हुआ है।

तालिका 3: भारत का प्रमुख देशों के साथ मर्चेन्डाइज्ड व्यापार संतुलन							
अमेरिकी डॉलर बिलियन में कीमत							
क्रम संख्या	देश	निर्यात		आयात		व्यापार संतुलन	
		अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)	अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)	अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)
1	यूएसए	35.6	31.3	25.1	16.3	10.5	15.0
2	बांग्लादेश	5.3	5.0	0.8	0.6	4.5	4.4
3	नेपाल	4.8	3.4	0.5	0.4	4.3	3.0
4	यूके	5.7	4.6	4.5	2.6	1.2	2.0
5	नीदरलैंड	5.7	3.8	2.4	1.9	3.4	1.9
6	श्रीलंका	2.6	2.1	0.6	0.4	2.0	1.7
7	तुर्की	3.4	2.3	1.5	0.9	1.9	1.4
8	कतर	0.8	0.8	6.0	4.6	-5.3	-3.8
9	दक्षिण कोरिया	3.1	2.9	10.9	7.1	-7.8	-4.2
10	इंडोनेशिया	2.5	2.7	9.6	7.3	-7.0	-4.6
11	स्विट्ज़रलैंड	0.8	0.9	12.8	5.8	-12.0	-4.9
12	सऊदी अरब	3.8	3.6	18.2	9.2	-14.4	-5.6
13	इराक	1.3	1.0	15.4	7.6	-14.1	-6.6
14	चीन	11.5	13.6	46.9	38.8	-35.4	-25.2

स्रोत: डीओसी

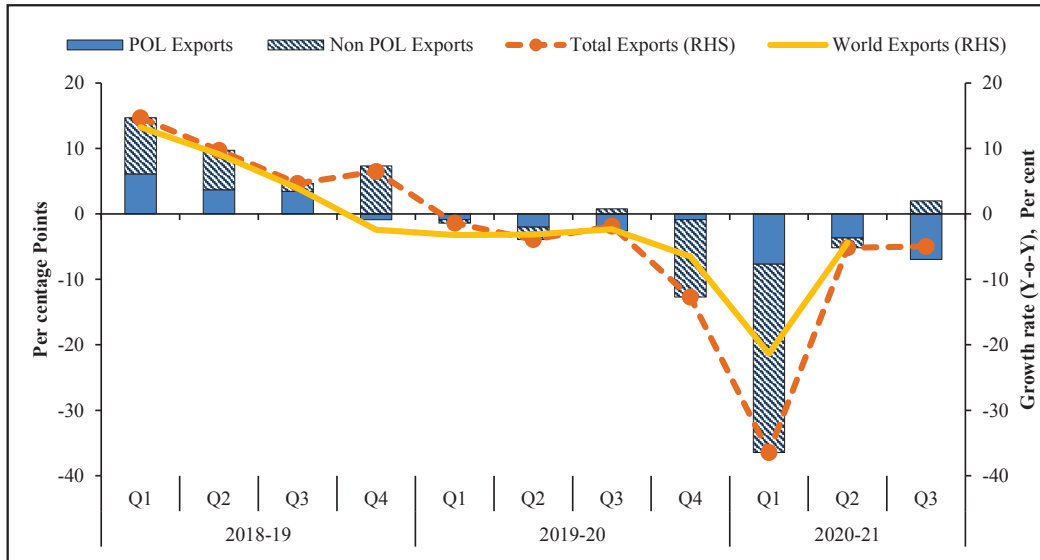
नोट: आर संशोधित, पी: (अनंतिम)

मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट

3.11 अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान कुल निर्यात यूएस \$ 200.8 बिलियन हुआ। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान (-) 2.4 प्रतिशत की तुलना में (-) 15.7 प्रतिशत का संकुचन हुआ है। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) निर्यात का समीक्षाधीन अवधि के दौरान निर्यात प्रदर्शन में नकारात्मक योगदान रहा है जबकि ये कुल निर्यात का लगभग 10-15 प्रतिशत है। पीओएल निर्यात में गिरावट काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से आई है, जो पिछले साल की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान (-) 54.0 प्रतिशत की गिरावट के साथ तथा वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही तक (-) 28.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ बनी रही। दूसरी ओर, गैर-पीओएल निर्यात, जिसने 2020-21 के प्रथम तिमाही में निर्यात के संकुचन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, सकारात्मक रूप से बदल गया और तीसरी तिमाही (चित्र 4) में निर्यात निष्पादन में सुधार करने में मदद की। गैर-पीओएल निर्यातों के भीतर, कृषि और संबद्ध

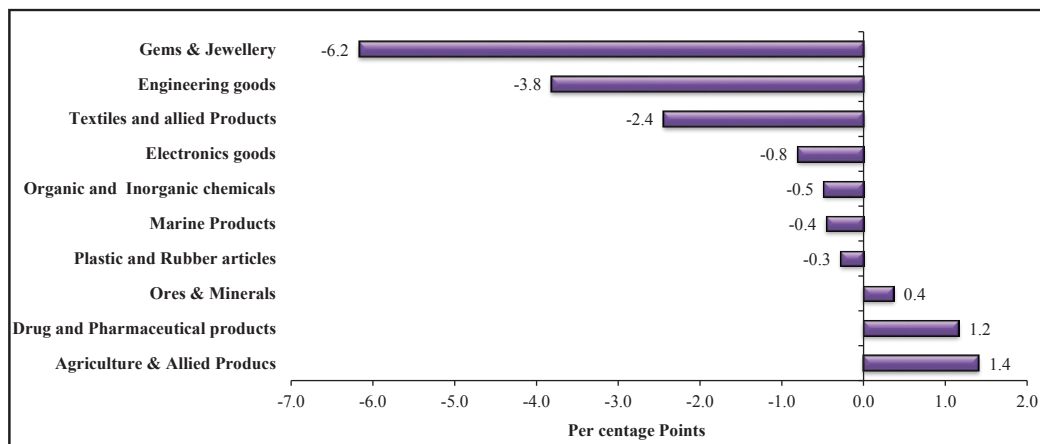
उत्पादों, दवाओं और दवा और अयस्कों और खनिजों में लचीला और अभिलिखित विस्तार साबित हुआ। हालांकि, प्रमुख वस्तुएं जैसे कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा और संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न और आभूषण ने निर्यात वृद्धि को नीचे खींच लिया (चित्र 5)।

चित्र 4 : निर्यात वृद्धि में सापेक्ष योगदान



स्रोत : वाणिज्य विभाग और विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण परिकलन

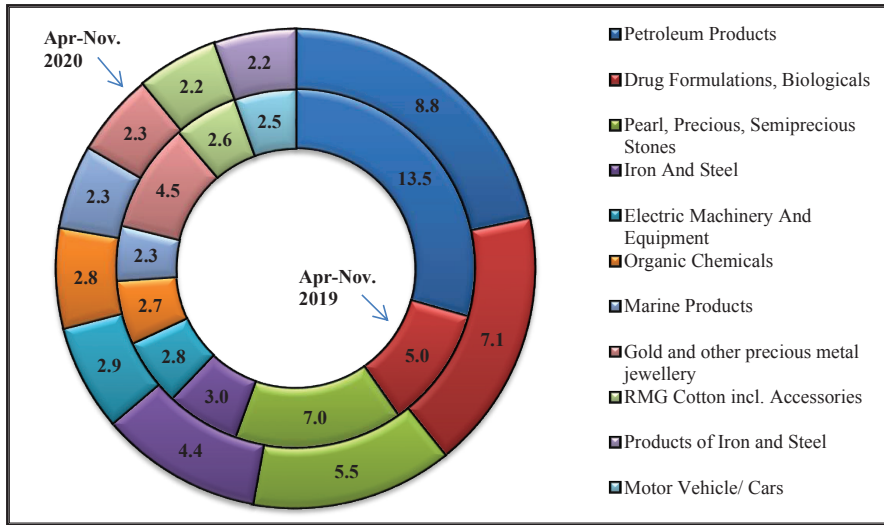
चित्र 5 : 2020-21 (अप्रैल-नवंबर) (पी) में गैर-पीओएल निर्यात वृद्धि में सापेक्ष योगदान



स्रोत : वाणिज्य विभाग के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण परिकलन

3.12 दवा (ड्रग) फार्मूलेशन, जैविक उत्पादों में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है और हाल के महीनों में इनमें निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। इसके कारण अप्रैल-नवंबर 2020 में इसकी हिस्सेदारी अप्रैल-नवंबर 2019 के 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गई, जिससे यह शीर्ष 10 निर्यात वस्तुओं (चित्र 6) के बीच दूसरी सबसे बड़ी निर्यात की गई वस्तु बन गई। इससे यह साबित हो रहा है कि भारत में 'दुनिया की फार्मसी' बनने की क्षमता है (बॉक्स 1)। आयरन एंड स्टील एक अन्य कमोडिटी है जिसका शेयर उक्त अवधि में 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, महामारी से संबंधित व्यवधानों ने मोटर वाहन/कारों के निर्यात में तीव्र गिरावट का नेतृत्व किया, क्योंकि अब यह क्षेत्र अप्रैल 2020 में निर्यातित शीर्ष 10 वस्तुओं में से एक नहीं रह गया है।

चित्र 6 : अप्रैल-नवंबर 2020 और अप्रैल-नवंबर 2019 में टॉप 10 एक्सपोर्ट कमोडिटीज [प्रतिशत में शेयर]



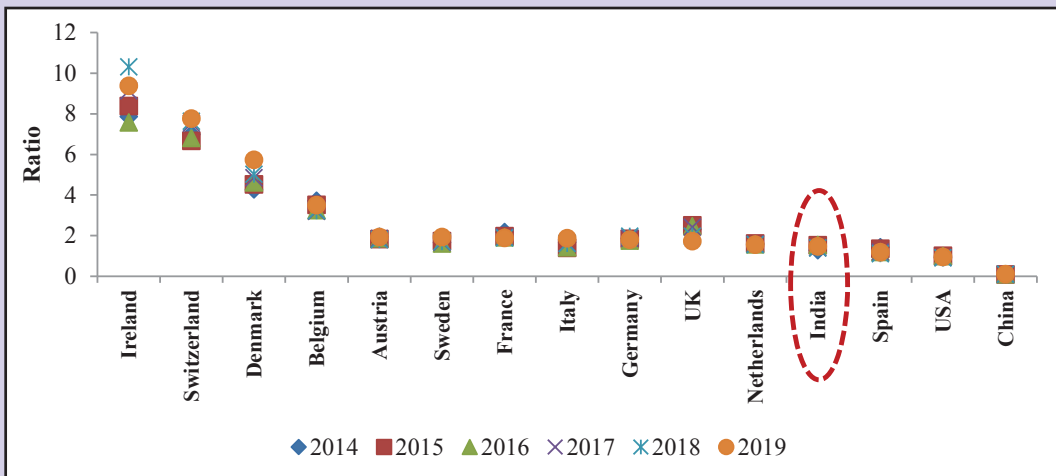
स्रोत: वाणिज्य विभाग

बॉक्स I: भारत की वैश्विक फार्मेसी बनने की सम्भावनाएं

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया में तीसरे स्थान पर है; यह मात्रा के मामले में, चीन और इटली के बाद आता है और मूल्य के मामले में 14वीं सबसे बड़ा उद्योग है। भारत ने विश्व फार्मा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को दस वर्ष की अवधि के दौरान 2010 में 1.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2019 में 2.6 प्रतिशत कर लिया है। 2019 में विश्व फार्मा निर्यात में हिस्सेदारी के मामले में भारत 11 वे स्थान पर था और जर्मनी, स्वीटज़रलैण्ड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष तीन स्थानों पर थे।

भारत 2009 से अपने फार्मास्यूटिकल स्थिति में सतत एवम् दीर्घ आवधिक रिवील्ड कम्परेटिव (आर सी ए) का लाभ ले रहा है। हालांकि, क्रास-कंट्री परिप्रेक्ष्य में, भारत का रिवील्ड कम्परेटिव (आर सी ए) 12वें स्थान पर था (चित्र- बी1) इसके अतिरिक्त, भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का व्यापार विशेषज्ञता गुणांक (टी एस सी) का मूल्य उच्च स्तर पर है। यह 2014-15 से लगातार एक के आसपास है। टी एस सी के मूल्य -1 और 1 के बीच है, और उच्च टीएससी का मूल्य देश की सद्गुण निर्यात प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

चित्र - बी 1.1 15 बड़े फार्मा निर्यातकों के लिए आर सी ए (2019 तक)



स्रोत- व्यापार मानचित्र आंकड़ों पर आधारित

वैश्विक फार्मास्युटिकल बाजार 2023 तक 1.5 ट्रिलियन यू.एस. डालर से आगे निकल जाएगा। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग का वर्तमान मूल्य 41 बिलियन यू एस डालर है तथा 2024 तक इसमें यूएस \$65 बिलियन तथा 2030 तक लगभग यूए \$120-130 बिलियन तक की वृद्धि की संभावना है। प्रमुख कच्चे माल का बेस और कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता ने भारत को जेनेरिक दवाओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा भारत एक मात्र ऐसा देश है, जिसकी यूएसए के बाहर यूएस-एफ डी ए कम्प्लेंट फार्मा प्लांट (एपीआई सहित 262 से अधिक) की एक बड़ी संख्या है।

कोविड-19 ने भारत को “दुनिया की फार्मसी” के रूप में उभरने के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों मौहया कराएं हैं। अप्रैल-अक्टूबर, 2020 के दौरान भारत का फार्मास्युटिकल निर्यात कुल 11.1 बिलियन यू एस डालर है जिसमें 18.0 प्रतिशत थी। शानदान वृद्धि दर्ज की गई हैं, जबकि यह एक वर्ष पहले यह 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इससे अप्रैल-अक्टूबर में भारत के कुल निर्यात में फार्मास्युटिकल निर्यात की हिस्सेदारी 5.1 प्रतिशत से अप्रैल अक्टूबर-20 में 7.3 प्रतिशत तक बढ़ गई है। जिससे यह अब तीसरी सबसे निर्यात वस्तु बन गई है। कोविड-19 वेक्सीन की दूसरे देशों को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता ने भारत को वैक्सिन के निर्माण का एक केंद्र बना दिया है। यूएस-एफ डी ए से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय फार्मा कम्पनियों का पिछले नौ महीनों में सभी एब्रीवेटेड नए दवा आवेदन (एडीएनए) के लगभग 45% को मंजूरी दी है जो आने वाले वर्षों में निर्यात वृद्धि में मदद करेगी। हालांकि, महामारी ने ऐक्टिव फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) तथा “की स्ट्राटिंग सामग्री” (केएसएस) के स्रोत के लिए भारतीय दवा उद्योग के लिए चीन पर आवधिक निर्भरता को उजागर किया है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका और जैनेरिक पर भारतीय दवा निर्यात की असंगत निर्भरता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (पीएल आई) योजना शुरू कराने के लिए फार्मास्युटिकल दवाओं को दस प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है। यह थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए पहले से अधिसूचित पीएलआई योजनाओं के आलेख है, जिसका उद्देश्य क्रिटीकल के एस एम/ड्रग सामग्री (डीआई), एपीआई तथा चिकित्सा उपकरणों के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इन दोनों योजनाओं को फार्मास्युटिकल के साथ-साथ आस्थे (Asthe) चिकित्सा उपकरण उद्योग से अत्यधिक सराहनीय प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इसके अतिरिक्त, ड्रग पार्क तथा मेडिकल डिवाइस पार्क को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की भी घोषणा की गई है।

भारतीय फार्मा को महामारी से उत्पन्न हुए सुनहरे अवसर को भुनाने और “दुनिया की फार्मसी” के रूप में उभरने की आवश्यकता है। उद्योगों के व्यापक विकास के लिए एक अच्छी रणनीति में निम्नलिखित घटकों को समाहित करने की आवश्यकता है।

(i) बाजार के सन्दर्भ में व्यापक आधार के साथ-साथ उत्पाद वर्ग के रूप में: बायोसीमीलर जीन थैरेपी, तथा विशेषीकृत दवाएं एवम जापान, चीन, आफ्रिका, इन्डोनेशिया, रूस/सी आई एस देश में निर्यात बढ़ाना। ब्राजील तथा लेटिन अमेरिका जैसे बड़े तथा परम्परागत रूप से कमजोर बाजार भारतीय फार्मा उद्योग के लिए आगे पांव पसारने की एक शुरुआत हो सकते हैं।

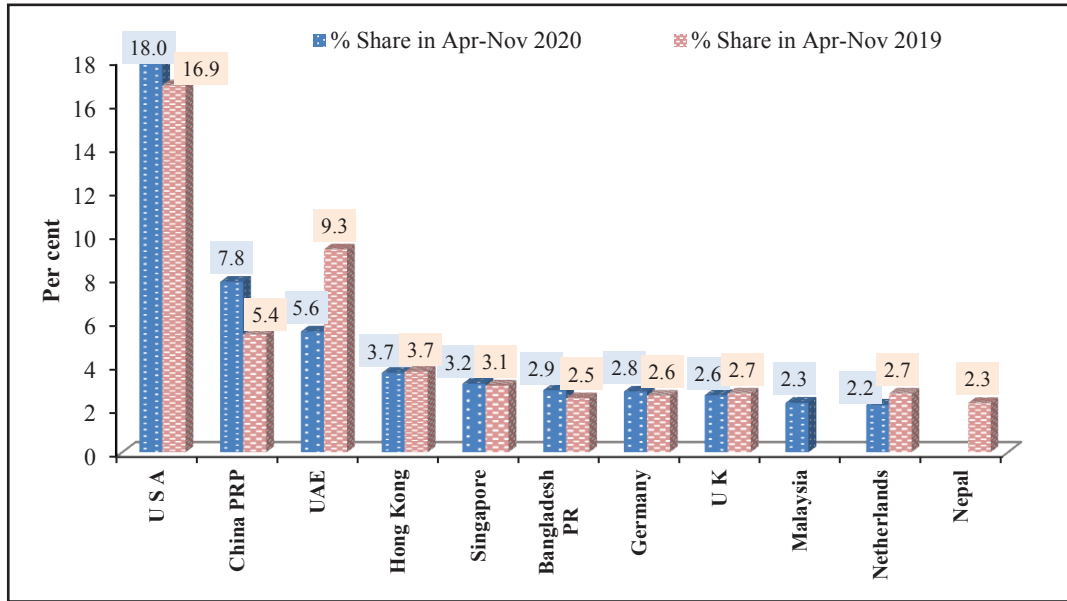
(ii) वर्तमान विनियामक तंत्र का पुनर्गठन और विभिन्न राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में (एन आई पी ई आर) में क्षमताओं का उन्नयन और निर्माण करना।

(iii) ग्रेटर आर एवं डी व्यय नोवल केमिकल एनटाईटीज (NCEs) से जेनेरिक में मूल्य क्षुंखला को आगे बढ़ाना।

संदर्भ भल्ला एस.एस. (2019) रिपोर्ट आफ द हाई लेवल एडवाइजरी गुपावाणिज्य विभाग भा.स.
इन्वेस्ट इंडिया से लिया गया: <https://www.inrestindia.gov.in/sectorpharmaceutical> में, महाजन वरूण, डी. के. नौरियल, एस. पी. सिंह, “ट्रैड परफॉरमेंस एण्ड रिसेल्वेड कम्पेरिटिव एडवांटेज ऑफ इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज इन न्यू रीजिम” आईपीआर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल एण्ड हेल्थकेयर मार्केटिंग 2015, <https://www.ipa-india.org/> डब्लू पी-कन्टेनट/अपलोड/2020/10/इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री-वे-फारवर्ड.पीडीएफ से लिया गया। “द इंडियन फार्मास्युटिकल उद्योग द वे फारवर्ड”, इंडियन फार्मास्युटिकल अलायेंस, जून 2019.

3.13 जहां तक शीर्ष निर्यात देशों का सम्बन्ध है, संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल-नवम्बर, 2020 में भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात बाजार के रूप से बना हुआ है, जबकि चीन अप्रैल-नवम्बर 2019 में तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। अप्रैल-नवम्बर 2019 में 5.4 प्रतिशत तथा अप्रैल 2020 में लगभग 7.8 प्रतिशत निर्यात चीन को किया गया। (चित्र-7) अंतिम वर्ष की तुलना में, शीर्ष के दस निर्यात देशों में मलेशिया नया जुड़ा है, जबकि शीर्ष के दस देशों में नेपाल का कोई भी स्थान है।

चित्र 7: अप्रैल-नवम्बर 2020 तथा अप्रैल-नवम्बर 2019 में शीर्ष दस निर्यात गंतव्य (प्रतिशत में हिस्सा)

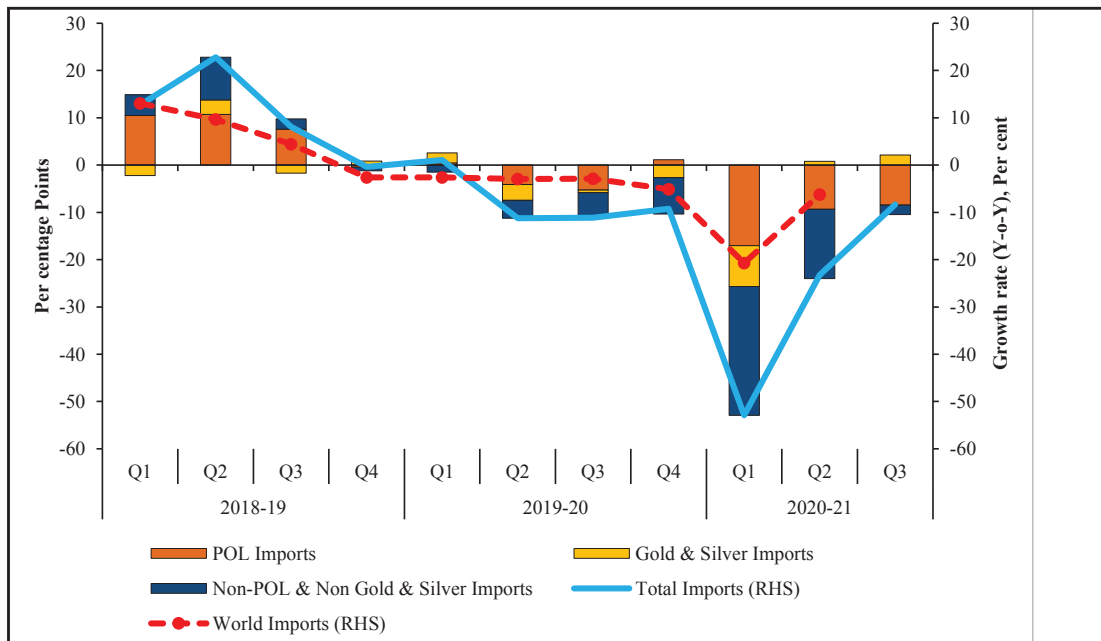


स्रोत- डीओसी

उत्पाद व्यापार आयात

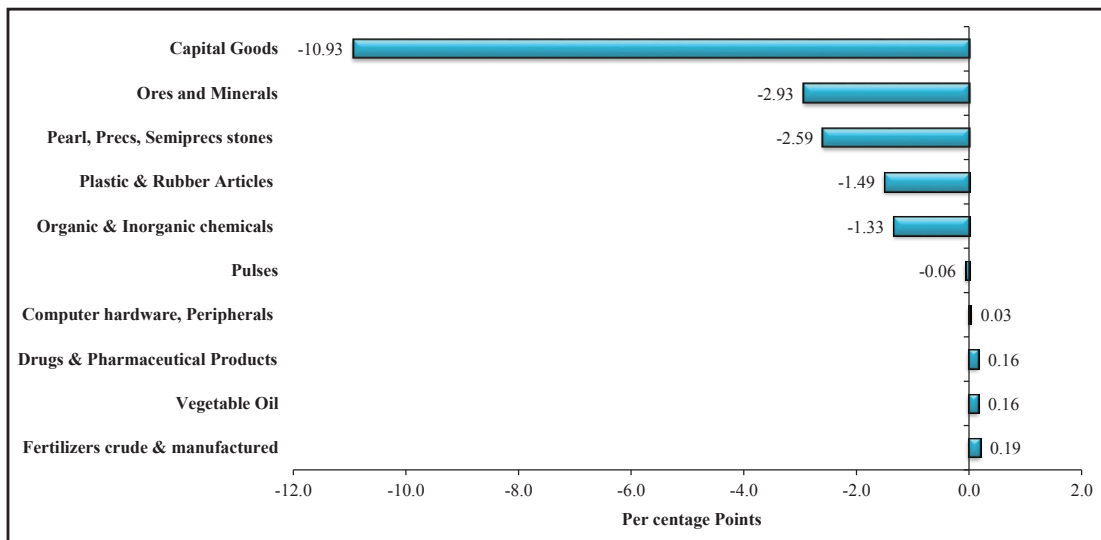
3.14 विगत वर्ष इसी अवधि के दौरान (-) 7.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2020 के दौरान (-) 29.1 प्रतिशत के संकुचन के साथ 258.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल आयात था। पी ओ एल आयात में स्पष्ट गिरावट है जो कुल माल के आयात के एक चौथाई के लगभग है और ये सभी प्रकार की निर्यात वृद्धि में गिरावट लाती है। (चित्र. 8)। इस अवधि के दौरान, पीओएल आयातों का मूल्य 53.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से (-) 44.5 प्रतिशत तक घटी है, जो (-) 16.7 प्रतिशत तक पी ओ एल आयात की मात्रा में कमी लाती है, तथा कच्चे तेल के मूल्य में (भारतीय बाजार) (-) 30.2 प्रतिशत की कमी लाती है। जबकि 2020-21 की पहली तिमाही (Q 1) में कुल व्यापार आयात (-) 52.9 प्रतिशत तक अनुबन्धित था, और दूसरी व तीसरी तिमाही (Q 2 व Q3) में संकुचन ढील की गति क्रमशः (-) 23.2 प्रतिशत तथा (-) 8.3 प्रतिशत रहा है। आयातों में यह सुधार सोने और चांदी के आयात में सकारात्मक वृद्धि और पी ओ एल गैर सोना और चांदी के संकुचन को कम करके योगदान दिया गया था। सोने और चांदी का आयात, भारतीय आयातों के लगभग 7-9 प्रतिशत की औसत का अनुबन्धन, 10.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2020-21 की (Q3) तीसरी तिमाही में 33.0 प्रतिशत की गतिशिल वृद्धि का साक्षी है। यह मुख्यरूप से अन्तर्राष्ट्रीय सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ है। उर्वरक, वनस्पति तेल, दवा एवं फार्मास्युटिकल और कम्प्यूटर हाइवेयर, सहायक उपकरणों ने गैर-पीओएल, गैर-साने, चांदी आयातों की वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया है जबकि पूंजीगत वस्तुओं ने इनकी कमियों में योगदान दिया है (चित्र-9)

चित्र-8: आयात वृद्धि में सापेक्ष योगदान



स्रोत: वाणिज्य विभाग एवं डब्ल्यू टी ओ के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण

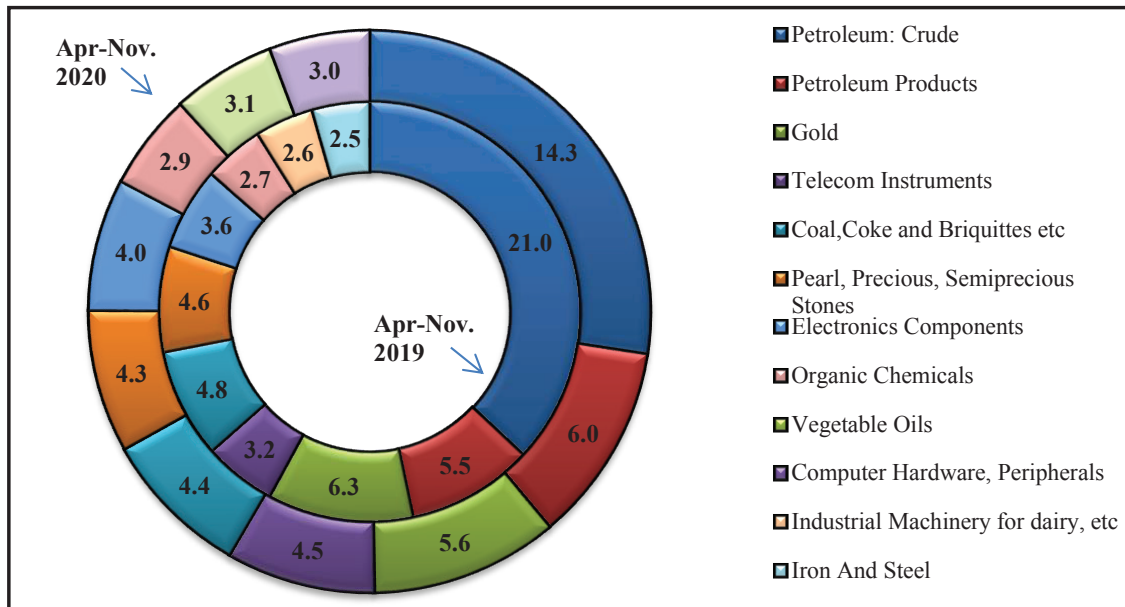
चित्र-9 2020-21 में गैर-पीओएल तथा गैर सोना एवं चांदी आयात की वृद्धि में प्रमुख वस्तुओं का सापेक्ष योगदान



स्रोत: वाणिज्य विभाग के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण

3.15 कच्चा पेट्रोलियम अप्रैल-नवम्बर 2020 में सबसे ज्यादा आयात की जाने वाली वस्तु बनी हुई है, जिसकी हिस्सेदारी 14.3 प्रतिशत है तथा साथ ही साथ अप्रैल नवम्बर 2019 (चित्र) में 21.0 प्रतिशत थी। सोने के आयात की हिस्सेदारी अप्रैल-नवम्बर 2020 में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.3 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत हो गई है, जिससे यह दूसरे स्थान से खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गया है। अप्रैल-नवम्बर 2020 में शीर्ष 10 आयात वस्तुओं की सूची में कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा पेरिफेरल नई वस्तु जुड़ी है। यह अब अधिक लोगों के घर से काम करने के कारण बढ़ी मांग से कुल आयातित वस्तुओं का 3.0 प्रतिशत है।

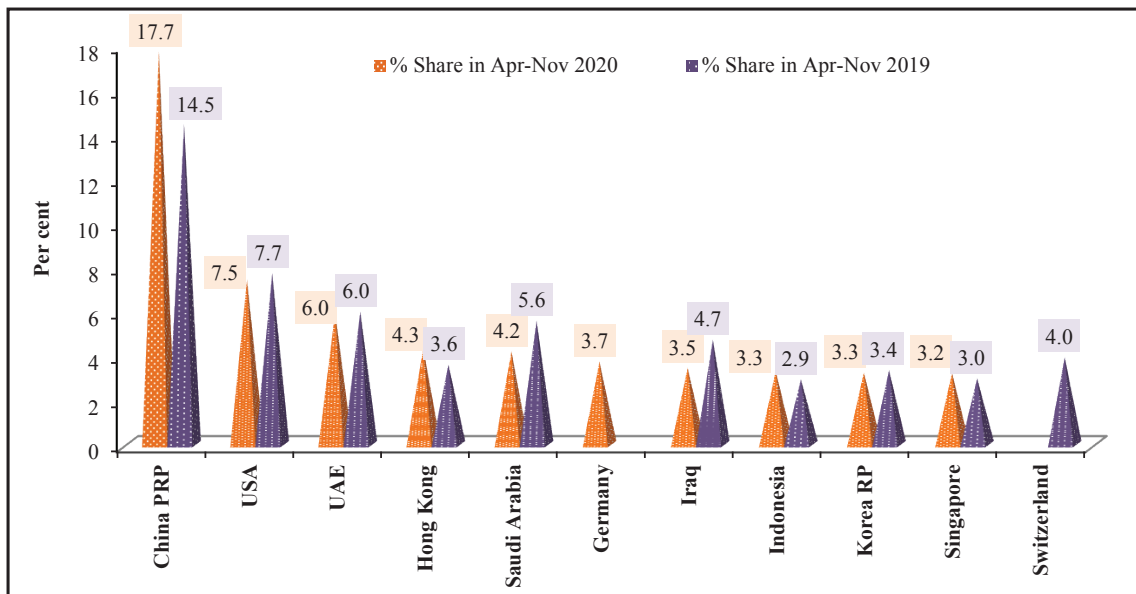
चित्र 10: अप्रैल-नवम्बर 2020 तथा अप्रैल-नवम्बर 2019 में दस शीर्ष आयातित वस्तुएं (हिस्सेदारी प्रतिशत में)



स्रोत: वाणिज्य विभाग

3.16 अप्रैल-नवम्बर 2020 में भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत के लिए मूल आयात करने वाले 10 शीर्ष देशों में, चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत बना। आयात की भागीदारी अप्रैल-नवंबर 2019 में 14.5 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-नवम्बर 2020 में 17.7 प्रतिशत हो गई। चित्र (11), जबकि स्वीटजरलैंड शीर्ष 10 आयात स्रोतों में शामिल नहीं है, जर्मनी 3.7 प्रतिशत कि कुल हिस्सेदारी के साथ सूची में नया जुड़ाव है।

चित्र 11: अप्रैल-नवम्बर 2020 तथा अप्रैल-नवम्बर 2019 में शीर्ष 10 आयात स्रोत (हिस्सेदारी प्रतिशत में)



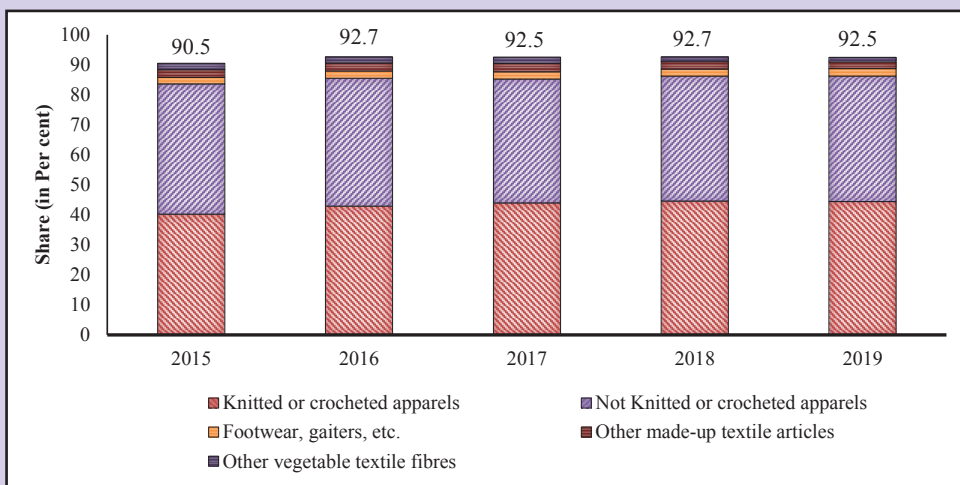
स्रोत: वाणिज्य विभाग

बॉक्स-2 भारत बनाम बांग्लादेश के निर्यात निष्पदान की तुलना

बांग्लादेश एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है क्योंकि इसकी 2011-19 के दौरान प्रभावशाली मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 8.6 रही है। जो भारत की तुलना में 0.9 प्रतिशत, तथा विश्व की तुलना में 0.4 प्रतिशत अधिक है। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की विश्व निर्यात में हिस्सेदारी 2011 में 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 0.3 प्रतिशत हो गई है।

शीर्ष पांच निर्यात वस्तुओं का निर्यात 2015 के बाद से बांग्लादेश के कुल निर्यात के 90 प्रतिशत से अधिक रहा। ये पांचों वस्तुएं मुख्य रूप से वस्त्र परिधान और फुटवियर उद्योग से सम्बन्धित है, यह अत्यधिक श्रम-गहन है और अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं (चित्र) 32.1) दूसरी और, निर्यात के मामले में, भारत का व्यापार अधिक व्यापक है, क्योंकि शीर्ष पांच वस्तुएं संयुक्त रूप से कुल निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत योगदान करती है (चित्र बी 2.2) और ये वस्तुएं पूंजी और प्रौद्योगिकी गहन है।

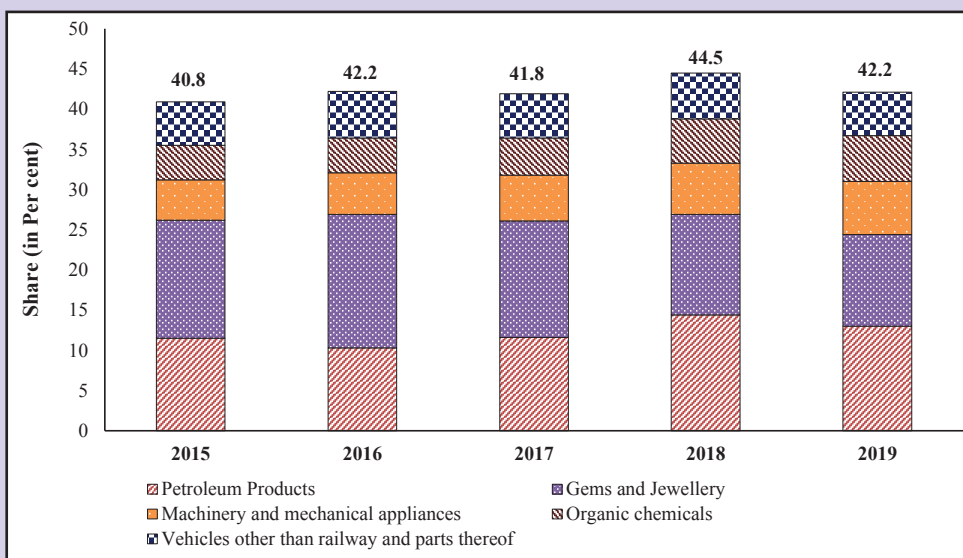
चित्र B 2.1 बांग्लादेश में शीर्ष पांच निर्यात वस्तुएं (हिस्सेदारी के रूप में)



स्रोत: ट्रेड मैप आंकड़ों पर आधारित

नोट: बांग्लादेश निर्यात टाईम श्रृंखला की अनुपलब्धता के कारण, मिरर टाईम श्रृंखला का प्रयोग हुआ

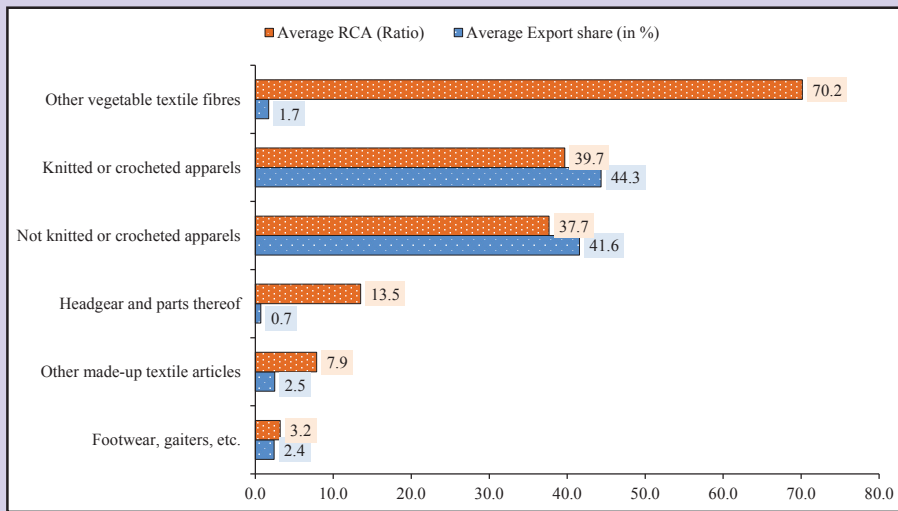
चित्रा B 2.2 भारत में शीर्ष पांच निर्यात वस्तुएं (हिस्सेदारी के रूप में)



स्रोत: ट्रेड मैप डाटा के आधार पर

वर्ष 2017 से 2019 तक पिछले तीन वर्षों के लिए औसत गणना के बाद शीर्ष 10 निर्यात वस्तुएं, जिनमें बांग्लादेश का सबसे अधिक आरसीए (RCA) था चित्र बी 2.3 में दर्शाया गया है। बांग्लादेश की शीर्ष पांच निर्यात वस्तुओं में यह चार वस्तुएं भी शीर्ष पर हैं (हिस्सेदारी एवं मूल्य के सम्बन्ध में)। यह रेखांकित करता है कि बांग्लादेश उन वस्तुओं का निर्यात करता है, जिनमें उसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अधिक है।

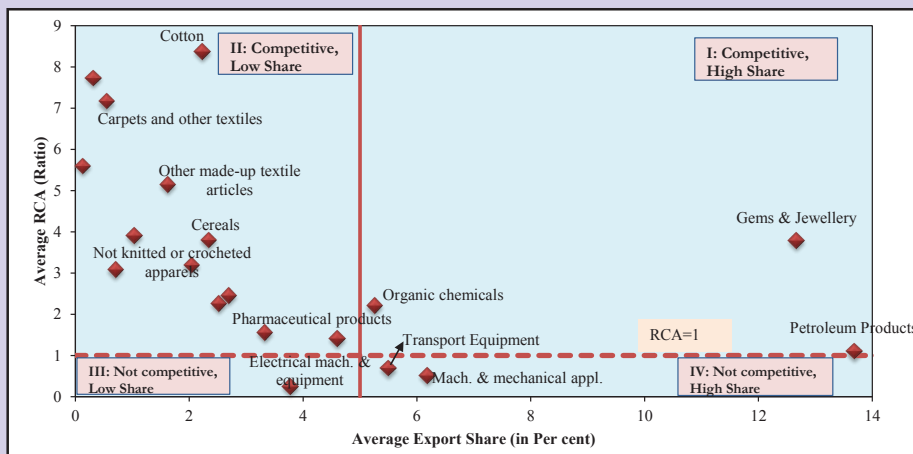
चित्र B 2.3: सबसे अधिक RCA शीर्ष निर्यात वस्तुएं तथा बांग्लादेश के निर्यात की हिस्सेदारी (2017-2019 का औसत)



स्रोत: ट्रेड अप डाटा पर आधारित

हालांकि, शीर्ष निर्यात वस्तुओं में से कोई भी वह नहीं है जिसमें भारत का शीर्ष आर सी ए है (चित्र B 2.4)। भारत की शीर्ष आर सी ए निर्यात वस्तुएं मुख्य रूप से श्रम-गहन हैं, जैसे कपास, कालीन, और अन्य वस्त्र आदि। (दूसरा क्वार्टेंट) जबकि भारत पेट्रोलियम उत्पादों, मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों जैसे पूंजी उत्पादों का अधिक निर्यात करता है। (चौथा क्वार्टेंट)

चित्र-B 2.4 भारत से सबसे अधिक आरसीए तथा निर्यात हिस्सेदारी वाली शीर्ष निर्यात वस्तुएं (2017-19 का औसत)



स्रोत: ट्रेड मैप डाटा पर आधारित

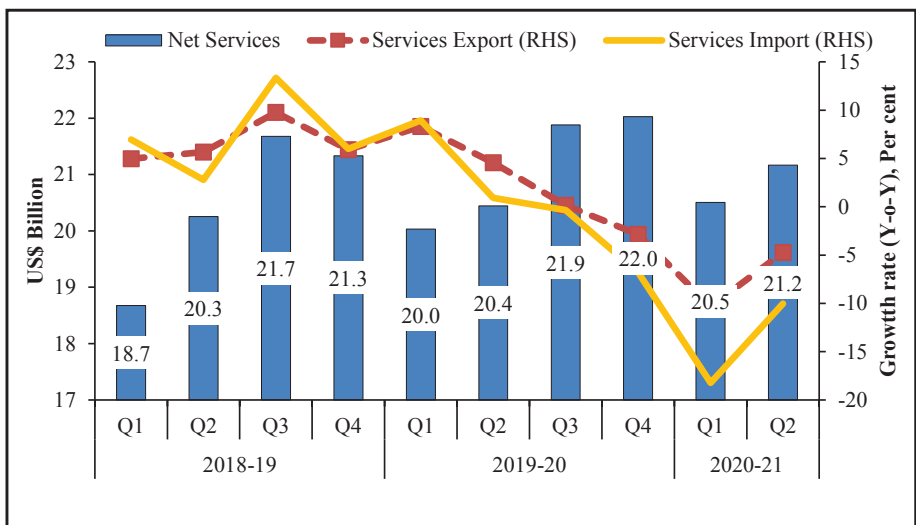
नोट: 5% (प्रतिशत) से अधिक हिस्सेदारी वाले निर्यात को बेंचमार्क के रूप में लिया गया है जबकि तीसरी सर्वाधिक निर्यात वस्तु की हिस्सेदारी 6% है।

उपर्युक्त साक्ष्य हमें ऐसे उत्पादों का निर्माण करने के लिए सबक देते हैं, जिनमें हम प्रतिस्पर्धी हैं। इस पैटर्न को आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अध्याय पांच में भी जांचा गया था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि कम विशेषज्ञता के साथ उच्च विविधकरण का अर्थ है कि भारत कई उत्पादों और भागीदारों पर अपने निर्यात का फौलाव बारिकी से कर रहा है।

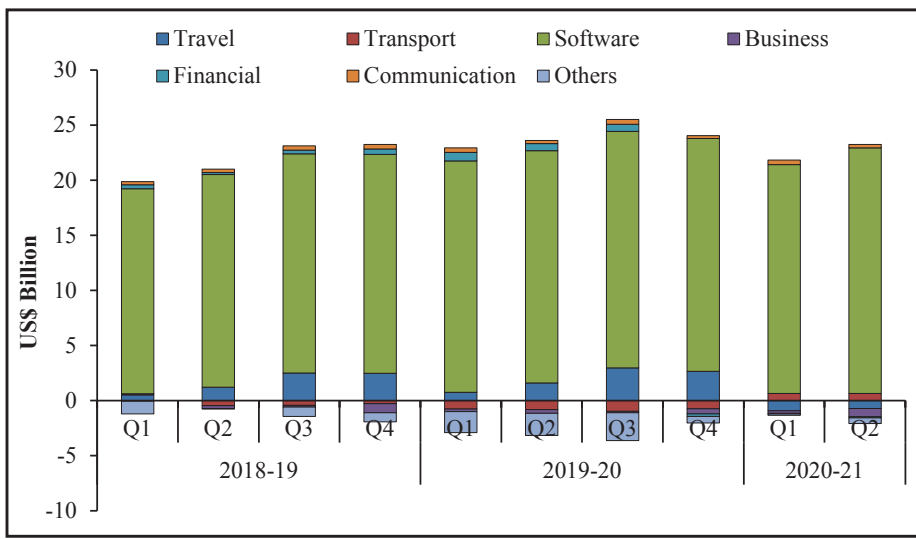
अदृश्य (इनविजिबल)

3.17 महामारी की शुरुआत और संक्रमण में गिरावट के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवजाही पर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण यात्रियों के आने में तेज संकुचन के बावजूद, अप्रैल से सितंबर 2020 तक नेट सेवाओं की प्राप्तियां एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 41.7 बिलियन अमेरिकी डालर पर स्थिर रहीं (चित्र 12क)। सेवा क्षेत्र प्रमुख रूप से सॉफ्टवेयर आधारित सेवाओं को दे रहा था, जो कुल सेवाओं के निर्यात का 49 प्रतिशत (चित्र 12ख) था।

चित्र 12क: निवल सेवा व्यापार



चित्र-12ख: निवल सेवा निर्यात के संरचना



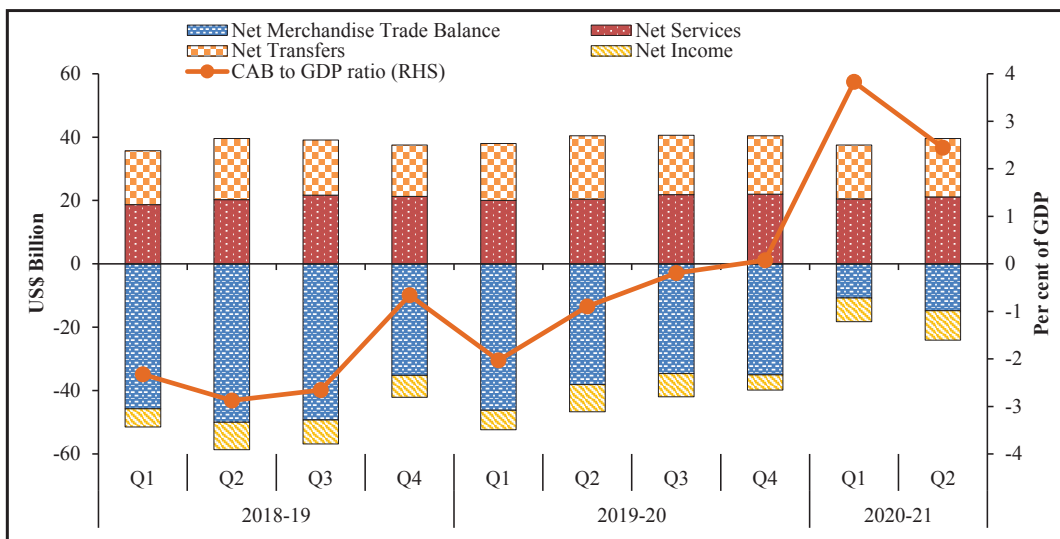
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.18 निवल निजी हस्तांतरण प्राप्तियां, विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा मुख्य रूप से प्रेषण का प्रतिनिधित्व करते हुए, वित्त वर्ष 2020-21 के एच-1: में कुल 35.8 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले 6.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विदेश में रह रहे प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारत की है (17.5 मिलियन) और भारत 2019 में 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता था। हालांकि विश्व बैंक के अनुसार, 2020 में कम से और मध्यम आय वाले देशों (LMICS) में प्रेषण के घटने के अनुमान 7.2 प्रतिशत है। भारत के लिये, 2020 में लगभग 8.9 प्रतिशत तक के 76 बिलियन डॉलर के कम होने का अनुमान है। वित्तिय और अन्य गैर उत्पादित परिसंपत्तियों के उत्पादन और स्वामित्व से जुड़े सीमापार के भुगतान के कारण नेट आउट गो, जो 2011-12 के बाद से ऊपर की बढ़ रहा था, 2010-20 में इसमें गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2020-21 में यूएसएस की प्राथमिक आय का शुद्ध बहिर्वाह 16.8 बिलियन था, जबकि एक वर्ष पहले यह इसी अवधि में 14.7 बिलियन अमेरिकी डालर था।

भुगतान शेष का चालू खाता

3.19 भारत का चालू खाता घाटा गत 10 वर्षों में औसतन सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत रहा है। इस चलन को उलटते हुए, वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में निचले व्यापार घाटे और शुद्ध अदृश्य प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि जैसे अन्य घटकों के कारण चालू खाता शेष में अधिशेष था (सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत) । वित्तीय वर्ष 2006-07 की चौथी तिमाही के बाद, 13 वर्षों के अंतराल के बाद यह तिमाही अधिशेष दर्ज किया गया। इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में सिलसिलेवार चालू खाता अधिशेष द्वारा जारी रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में, उत्पाद आयात में अत्यधिक संकुचन और यात्रा सेवाओं के लिए कम व्यय के कारण चालू प्राप्तियों (15.1 प्रतिशत) की तुलना में चालू 34.7 भुगतानों (30.8 प्रतिशत से) में तेज गिरावट हुई परिणामस्वरूप 34.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का चालू खाता अधिशेष (सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत) (चित्र) प्राप्त हुआ। माल और सेवाओं के आयातों में प्राप्त रूझानों से यह अपेक्षित है कि 17 वर्षों की अवधि के बाद भारत वार्षिक चालू खाता अधिशेष, जो सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2 प्रतिशत है, का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

चित्र 13: भारत की चालू खाता शेष का संयोजन



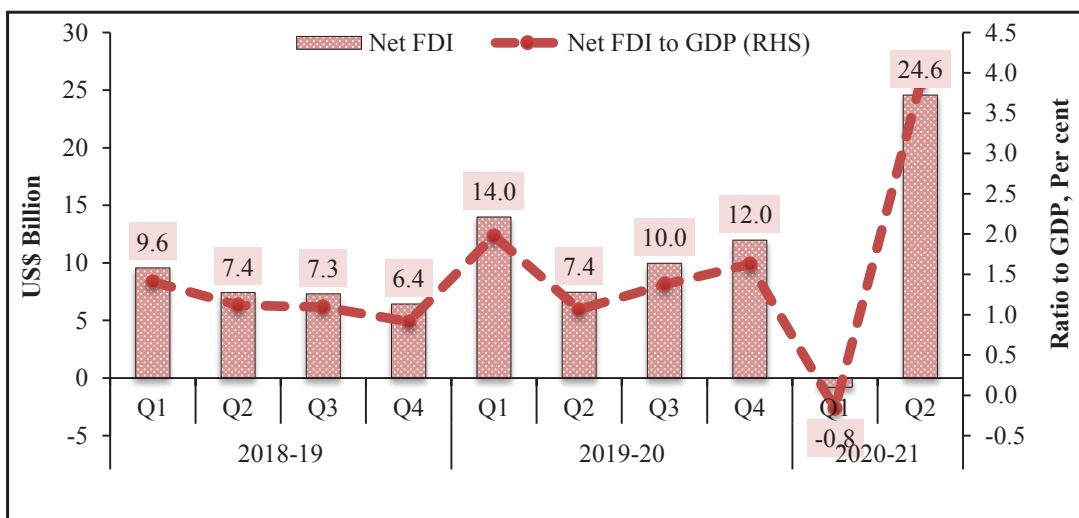
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

भुगतान शेष का पूंजीगत/वित्तीय खाता

3.20 विदेशी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) की शुद्ध अदायगी और बैंकिंग पूंजी में कमी के कारण शुद्ध पूंजी प्रवाह वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में 40.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विपरीत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सामान्य रहा। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 31.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शुद्ध विदेशी निवेश में वृद्धि देखी गई जो एक वर्ष पूर्व इसकी तुलना में 28.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

3.21 अप्रैल-अक्टूबर, 2020 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया जो 2019-20 के पहले सात महीनों की तुलना में 14.8 प्रतिशत अधिक रहा, जो वैश्विक निवेशकों के बीच पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति का समर्थन करता है (चित्र 14)। जहां तक सेक्टर-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संबंध है, अप्रैल-सितम्बर 2019 में 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने अप्रैल-सितम्बर 2020 में 17.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह को आकर्षित किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह के मामले में सिंगापुर सर्वाधिक निवेश करने वाला देश बना हुआ है, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका ने एक साल पहले इसी अवधि में चौथे स्थान की तुलना में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

चित्र 14: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

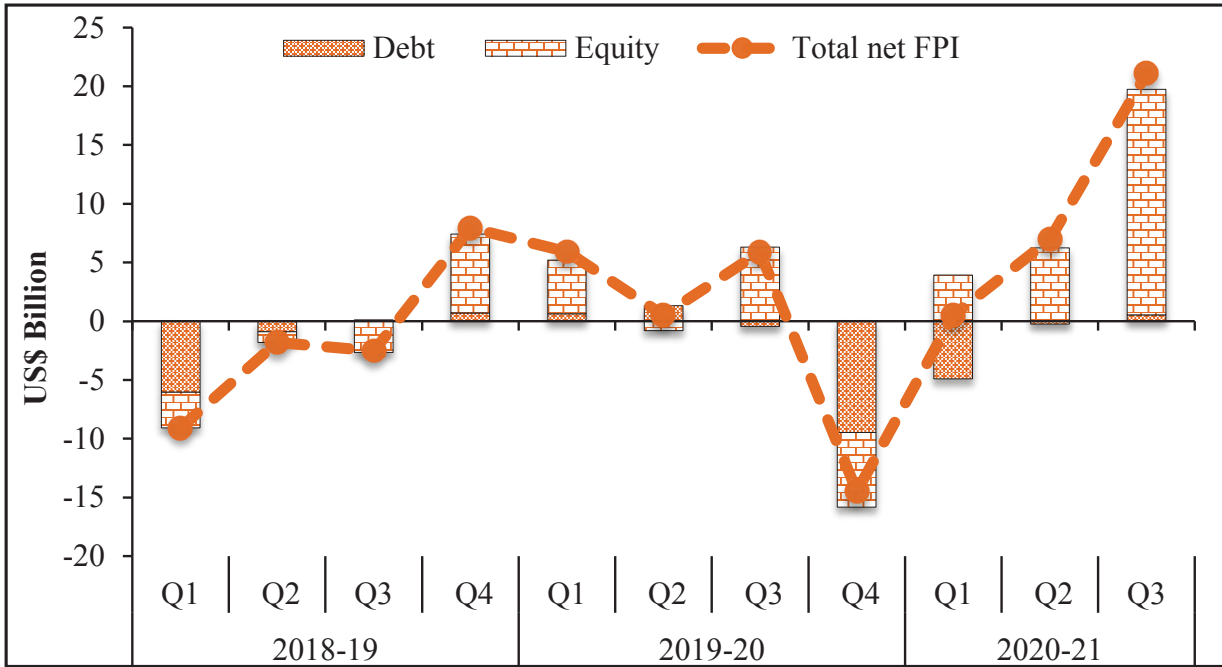


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: अक्टूबर 2020 में निवल एफडीआई इन्फ्लो 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था।

3.22 मार्च 2020 में अभूतपूर्व बिकवाली के बाद, महामारी की शुरुआत में वैश्विक निवेशकों के बीच मंदी की आशंका को दर्शाते हुए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में विशेष रूप से इक्विटी अंतर्वाह में मजबूत बदलाव देखा, पिछले वर्ष, अप्रैल-दिसंबर, 2020 में 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में गत वर्ष इस अवधि में शुद्ध एफपीआई 28.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई। भारतीय इक्विटी को प्रचुर मात्रा में वैश्विक नकदी द्वारा समर्थित किया गया है, बाद की तिमाहियों में बेहतर कॉर्पोरेट आय और कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन ने आर्थिक सुधार की संभावनाओं को फिर से प्रज्वलित किया है। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) वैश्विक मानक सूचकांक में भारतीय शेयरों की वृद्धि से विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने में मदद मिली है।

चित्र 15: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)



स्रोत: नेशनल सिक््योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)

नोट: कुल शुद्ध एफपीआई, ऋण, इक्विटी, हाइब्रिड और वीआरआर का योग है, हालांकि, उपरोक्त चार्ट में केवल ऋण और इक्विटी को दर्शाया गया है क्योंकि वे कुल शुद्ध एफपीआई के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं।

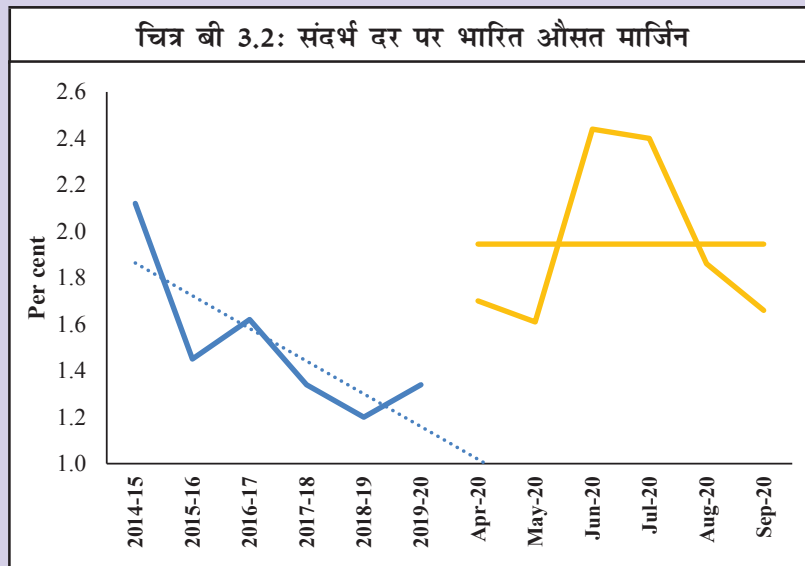
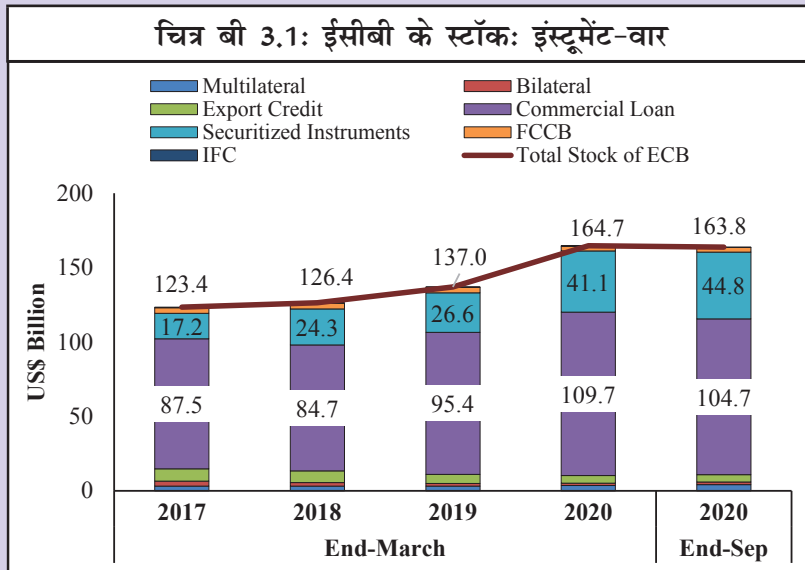
3.23 पूंजी प्रवाह के अन्य रूपों में, बैंकिंग पूंजी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया, जो 2019-20 की पहली छमाही के 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध बहिर्वाह से अधिक था। पुनर्भुगतान से बढ़े सकल संवितरणों के कारण और नए संवितरण से अधिक भुगतान के साथ, ईसीबी पर शुद्ध बहिर्वाह अप्रैल-सितंबर, 2020 में 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया। अनिवासी लोगों द्वारा जमा के कारण शुद्ध प्रवाह अप्रैल-सितंबर 2019 में 5.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

विदेशी कर्ज

3.24 सितंबर 2020 के अंत में, भारत का विदेशी कर्ज 556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया, जो कि मार्च 2020 के अंत के स्तर से 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (0.4 प्रतिशत) कम दर्ज किया गया। प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मूल्यहास के कारण हुए वैल्यूएशन लॉस को छोड़कर, विदेशी कर्ज में कमी 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही होती। विदेशी कर्ज के सबसे बड़े घटक के रूप में ईसीबी, सितंबर 2020 अंत में 207 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मार्च 2020 अंत के स्तर से 5.8 प्रतिशत संकुचित रहा (बॉक्स 3)। जबकि दूसरे सबसे बड़े घटक के रूप में अनिवासी जमा का स्टॉक मार्च 2020 अंत के स्तर की तुलना में 5.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ 137.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, व्यापार ऋण (आयात-वित्तपोषित) 2.0 प्रतिशत की कमी के साथ 99.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर तीसरा सबसे बड़ा घटक रहा। सरकारी कर्ज मार्च 2020 अंत में 100.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ कर 103.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

बॉक्स 3: ईसीबी-नीति की क्रमिक सुगमता

ईसीबी बकाया, मार्च 2020 अंत के 164.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में सितंबर 2020 अंत में 163.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ कम था। अधिकांश ईसीबी वाणिज्यिक ऋण और प्रतिभूति उधारों (91.2 प्रतिशत) (चित्र बी 3.1) के रूप में था जो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर (77.2 प्रतिशत) में था और गैर-वित्तीय निगमों की पहुंच में था (74.5 प्रतिशत)। ईसीबी की औसत परिपक्वता 6 वर्ष थी, अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान पंजीकृत ऋणों के लिए संदर्भ दर पर मासिक भारित औसत मार्जिन के औसत से मापी गई ईसीबी की लागत, 1.9 प्रतिशत थी जो हाल के वर्षों की तुलना में अधिक थी (चित्र बी 3.2)।



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

साहित्य (आचार्य V, अन्य, 2015; वर्मा और प्रकाश, 2011 तथा रे, अन्य, 2017) भारतीय संदर्भ ईसीबी के उत्प्रेरकों के रूप में देश-विशिष्ट अज्ञात (पुश) कारकों के साथ-साथ जेनेरिक और वैश्विक (पुल) कारकों की पहचान करता है। देश-विशिष्ट कारकों में घरेलू वास्तविक आर्थिक कार्यकलापों, विनिमय दर, ब्याज दर तथा मुद्रास्फीति, घरेलू कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार की स्थिति, पूंजी खाते के संदर्भ में खुलेपन की डिग्री और नियामक ढांचा शामिल है। वैश्विक वित्तीय स्थितियां जिनमें ब्याज दरें, वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति

शामिल हैं, पुल कारकों में से हैं। तदनुसार 2020-21 की पहली छमाही के दौरान आर्थिक कार्यकलापों में मंदी, ईसीबी के लिए भारत सतत, इच्छा को कम करने का कारण हो सकता है। चालू कोविड-19 महामारी से विदेशी वाणिज्यिक उधारकर्ता की निर्यात आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस तरह की आमदनी के कमजोर पड़ने पर, उनकी पुर्नभुगतान क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे संभावित संवेदनशीलता का स्रोत आगे बढ़ेगा।

बड़े निवेश की आवश्यकताओं के साथ पूंजी की कमी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, यह भारत की दीर्घकालिक नीति है कि पूंजी अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए ऐसी घरेलू बचत को बढ़ाया जाए जिसका झुकाव उन प्रवाहों की ओर हो जो स्थिर, दीर्घकालिक हो और जो अचानक ठहराव तथा परिवर्तन से कम से कम प्रभावित हो। तदनुसार, अन्य विषयों के साथ अभिप्रेरण अंतिम उपयोग के विनियमन के साथ जीडीपी युग्मित अनुपात के रूप में एक सक्रिय सीमा निर्धारण द्वारा प्रतिष्ठानों को विदेशी कर्ज लेने में सक्षम बनाते हुए औसत न्यूनतम परिपक्वता को निर्धारित कर अनिवार्य बचाव व्यवस्था और रोल ओवर रिस्क द्वारा मुद्रा जोखिम को कम से कम करता है। यह व्यापक प्रतिमान व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्षों में विकसित हुआ है। इस व्यापक प्रयास के एक अभिन्न अंग के रूप में, उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के आधार को विस्तृत करते हुए और सभी पात्र उधारकर्ताओं को समान अवसर प्रदान करने तथा मध्यस्थता के दायरे का हटाकर एक नई और सरल ईसीबी नीति को मार्च 2019 में अस्तित्व में लाया गया। इसके अलावा, विदेशी वाणिज्यिक उधारकर्ताओं को उनकी रूचि और पूंजीगत जोखिम को कम करने में सक्षम करने के लिए भारत में वित्तीय बाजारों के विकास को उचित महत्व दिया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत कारपोरेट-उधारकर्ता संवेदनशीलता से उत्पन्न अन्य हितधारकों के लिए संभावित प्रणाली स्थिरता जोखिम को कम करने के लिए वृद्धिशील विदेशी पूंजी देयता वाले प्रतिष्ठानों के लिए बैंकों के एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील प्रावधान और पूंजी आवश्यकताओं के लिए विनियामक सहायता ली गई है।

भारत के विदेशी ऋण 2019-20 की स्थिति पर रिपोर्ट में दस्तावेज के रूप में व्यापार करने के मामले में सुधार के दृष्टिकोण से ईसीबी के अंतिम उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक प्रगतिशील युक्तिकरण और उदारीकरण किया गया है। 16 जनवरी, 2019 से प्रभावी मौजूदा नीति के अनुसार, ईसीबी से संबंधित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और रुपये के ऋण के पुनः भुगतान के लिए विशिष्ट पात्र उधारकर्ताओं के लिए छूट दी गई है। पुनर्वित्त की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब मूल ऋण की बकाया परिपक्वता (आर्थिक ऋणों के मामले में भारित परिपक्वता) को कम नहीं किया जाता है और नई ईसीबी की सभी लागत वर्तमान ईसीबी की सभी लागत (अधिक ऋणों के मामले में भारित औसत लागत) से कम होती है। इसके अलावा, केवल उच्च रेटेड कारपोरेट्स (एएए) और महारत्न/नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मौजूदा ईसीबी के पुनर्वित्त में भाग लेने की अनुमति है।

आईसीई बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन (आईबीए), जो एलआईबीओआर को संकलित और इसकी देखरेख करता है, का मानना है कि 2021 के अंत में एक सप्ताह और दो महीने की अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर सेंटिंग समाप्त हो जाएगी तथा शेष अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर पैन्ल योजना के 18 महीनों बाद, जून 2023 अंत में बंद हो जाएगी। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि सितंबर 2020 के अंत में एलआईबीओआर-लिंकड ईसीबी/एफसीसीबी अनावरण मुद्राओं (यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, सीएचएफ और ईयूआर) में अमेरिकी डॉलर 81.8 अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जिसमें से लगभग 57.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ईसीबी/एफसीसीबी के रूप में ऋण अनुबंध दिसम्बर 2021 अंत तक समाप्त हो जाएंगे। जैसाकि वैश्विक स्तर पर वित्तीय अनुबंध में एलआईबीओआर-ऋण और व्युत्पन्न अनुबंध दोनों, का उल्लेख है, वह लागू रहेगा; उचित फॉलबैक भाषा को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए समाप्ति पर पुनर्विचार करना आवश्यक होगा।

संदर्भ

Acharya V, Cecchetti, S., Gregorio, J., Kalemli - Ozcan, S., Lane, P., & Panizza, U. (2015). *Corporate Debt in emerging economies: A Threat to Financial Stability*. Retrieved from <https://www.cigionline.org/sites/default/files/ciepr2015towe.pdf>

John Hawkins and Philip Turner. (2000). *Managing foreign debt and liquidity risks in emerging economies: an overview*. BIS.

Ministry of Finance. (2020). *India's External Debt - A Status Report: 2019-2020*.

RBI. (2020). *LIBOR: The Rise and the Fall*. Bulletin, November.

Verma, R., & Prakash, A. (2011). Sensitivity of Capital Flows to Interest Rate Differentials: An Empirical Assessment for India. *RBI Working Paper Series No. 7*. Retrieved 06 15, 2018, from <https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=13364>

3.25 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण मार्च 2020 अंत में 20.6 प्रतिशत से सितंबर 2020 अंत में 21.6 प्रतिशत के साथ थोड़ा बढ़ा (तालिका 4)। हालांकि, रिजर्व्स² में अधिक वृद्धि के कारण कुल विदेशी मुद्रा भण्डार का अनुपात और अल्पकालिक ऋण (मूल और बचत) में सुधार हुआ। विदेशी ऋण के कुल स्टॉक में अल्पकालिक ऋण मूल परिपक्वता का हिस्सा, जो संभावित ऋण सुभेद्यता का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है, में भी सुधार हुआ है। हालांकि चालू प्राप्तियों को दर्शाते हुए, ऋण सेवा अनुपात (मूल पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान), मार्च 2020 अंत में 6.5 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2020 अंत में बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गया।

तालिका 4: बाह्य ऋण सुभेद्यता सूचक (प्रतिशत जब तक अन्यथा संकेत न दिया जाए)

सूचक	मार्च अंत				सितंबर अंत
	2013	2018	2019	2020 (सं.)	2020 (अनं.)
कुल विदेशी कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	529.3	543.1	558.2	556.2
जीडी का विदेशी ऋण	22.4	20.1	19.8	20.6	21.6
कुल ऋण का अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता)	23.6	19.3	20	19.1	18.5
कुल ऋण का अल्पकालिक ऋण (बचत परिपक्वता)	42.1	42.0	43.4	42.4	44.6
कुल ऋण का रियायती ऋण	11.1	9.1	8.7	8.8	9.0
कुल ऋण का रिजर्व	71.3	80.2	76	85.2	97.4
रिजर्व का अल्पकालिक ऋण का अनुपात	33.1	24.1	26.3	22.5	19.0
रिजर्व का अल्पकालिक (बचत परिपक्वता)	59	52.3	57	49.5	45.5
ऋण सेवा अनुपात	5.9	7.5	6.4	6.5	9.7

स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय

नोट: आर: संशोधित, पी: अर्न्तम

बाक्स 4 : इंडियाज़ एक्सटर्नल डेब्ट: स्टॉक-टेकिंग एण्ड द वे फारवर्ड

जून 2020 अंत में दुनिया का कुल विदेशी ऋण 89 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था जो एक तिमाही पहले (2.2 प्रतिशत) की तुलना में मार्च 2020 अंत के स्तर से 1.0 प्रतिशत की कम दर से बढ़ा है। कुल विदेशी ऋण स्टॉक के 23.9 प्रतिशत के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक ऋणग्रस्त देश है। जून 2020 अंत तक 554.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित स्टॉक के साथ भारत को वैश्विक रूप से 23वें स्थान पर रखा गया है। विशेष डाटा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) की रिपोर्ट तैयार करने वाले देशों के बीच, जून 2020 अंत तक भारत के विदेशी ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल का विश्लेषण यह रेखांकित करता है कि भारत का अल्पकालिक ऋण अंश, 18.9 प्रतिशत है जो न केवल 24.2 प्रतिशत के औसत अंश से कम है, अपितु किसी भी शीर्ष 20 ऋणी देशों से भी कम है। इसके अलावा, एसडीडीएस और सामान्य डेटा प्रसार मानक (जीडीडीएस) देशों के मध्य, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी सेक्टर की हिस्सेदारी जून 2020 अंत में 18 प्रतिशत थी जो साधारण है और औसत हिस्सेदारी, 29.7 प्रतिशत से कम है।

सैद्धांतिक साहित्य, विदेशी ऋण और विकास के बीच “लाफ़र कर्व” संबंध का सुझाव देता है, जिसमें विदेशी ऋण के निवेश और विकास पर एक निश्चित सीमा स्तर तक साकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हालांकि इस स्तर के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव हो जाता है। इस गैर रेखीय संबंध में अनिश्चितता के एक तत्व को दर्शाते हुए, ऋण को अधिकतम या विकास के अधिकतम स्तर की एक श्रेणी की पहचान की जाती है। कोहेन (1997) ने पाया कि अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए, जीडीपी को विदेशी ऋण का 50 प्रतिशत और निर्यात को ऋण का 200 प्रतिशत वह परिवर्तन बिंदु हो सकता है जहां गैर-रेखिकता प्रभावी हो। विकासशील और मध्यम-आय वाले देशों के आधार पर पेटिलो, अन्य (2002, 2011), का तर्क है कि विदेशी ऋण का औसत प्रभाव निर्यात के लगभग 160-170 प्रतिशत या सकल घरेलू उत्पाद के 35-40 प्रतिशत पर नकारात्मक हो जाता है। दूसरी ओर, बेनेडिक्ट, अन्य (2003) ने पाया कि कम आय वाले देशों के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30-37 प्रतिशत का शुरुआती स्तर और निर्यात का लगभग 115-120 प्रतिशत इष्टतम है। साहित्य की एक अन्य धारा इस बात पर प्रकाश डालती है कि अच्छी नीतियों और मजबूत संस्थानों वाली देशों में उच्च थ्रेसहोल्ड होते हैं और खराब तथा कमजोर नीतियों और संस्थानों वाले देशों में कम थ्रेसहोल्ड होते हैं (कॉर्डेला, अन्य, 2010)। सबसे प्रसिद्ध धारा जिसे साहित्य में महत्व दिया गया है तथाकथित डेब्ट आवरहेडिंग है इसके द्वारा विदेशी ऋण, विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, देशों की पुनर्भुगतान क्षमता से भविष्य के विदेशी ऋण अधिक हाने की संभावना होने पर अपेक्षित ऋण सेवा देश के उत्पादन स्तर को तेजी से रोक देगी, जिससे निवेश पर लाभ कम होगा, जिससे नए घरेलू और विदेशी निवेश हतोत्साहित होंगे और निवेश की गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी।

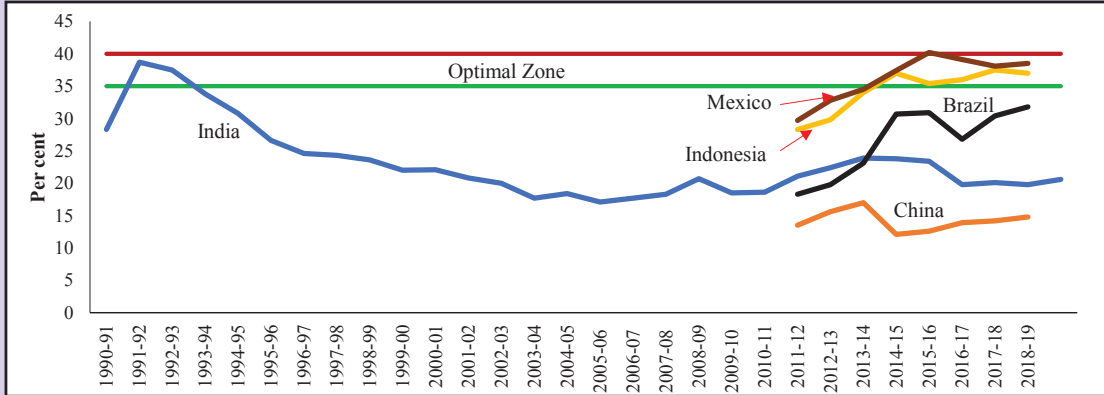
पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी अनुपात में भारत का विदेशी ऋण इष्टतम जोन से कम रहा है, जैसा कि मार्च 1992 अंत के 38.7 प्रतिशत से यह मार्च 2006 अंत में 17.1 प्रतिशत कम आ गया (चित्र बी 4.1)⁴। 2010 के दशक की शुरुआत में यह 23 प्रतिशत के आसपास सीमित रहा। (चित्र बी 4.2) यह मार्च 2020 अंत तक 20.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। चीन को छोड़कर, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भारत की तुलना में अधिक अनुपात है।

निर्यात अनुपात के प्रति भारत का विदेशी ऋण संकट वर्ष 1992 के बाद से निरंतर नीचे गया है, हालांकि यह हाल के वर्षों में ऊपर चढ़ा है और अब इष्टतम जोन के आस-पास है। यह याद रखने की आवश्यकता है कि इष्टतम जोन विकास को इंगित करता है जो स्थिर शासन द्वारा प्रदत्त दीर्घकालिक रूपरेखा से संभव है।

3 विशेष डेटा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) और सामान्य डेटा प्रसार मानकों के तहत प्रतिवेदित देशों सहित (जी डी डी एस)

4 इस संदर्भ में माना गया इष्टतम जोन, पेटिलो, अन्य, 2002 और 2011 से है जो विकासशील देशों से संबंधित है।

चित्र बी 4.1: भारत और चयनित विकासशील देशों में जीडीपी की ओर विदेशी ऋण का अनुपात: इष्टतम सीमा[@] बनाम वास्तविक

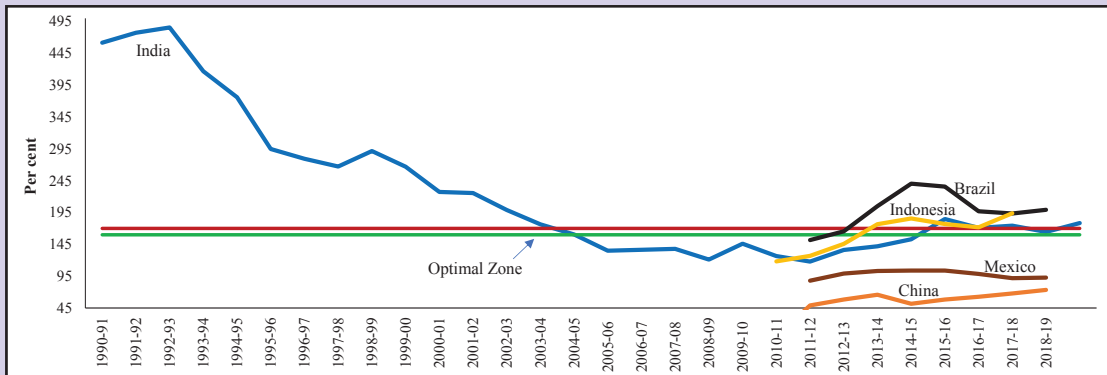


*भारत के अलावा देशों के लिए यह सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) अनुपात की ओर विदेशी ऋण है

[@] पैटिलो, अन्य, 2002 और 2011 से

स्रोत: भारत के विदेशी ऋण और अंतरराष्ट्रीय ऋण आंकड़ों पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट: विभिन्न संस्करण

चित्र बी 4.2: भारत और चयनित विकासशील देशों में निर्यात की ओर विदेशी ऋण का अनुपात: इष्टतम सीमा[@] बनाम वास्तविक



[@]पैटिलो, अन्य, 2002 और 2011

स्रोत: भारत के विदेशी ऋण और अंतरराष्ट्रीय ऋण आंकड़ों पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट: विभिन्न संस्करण

संदर्भ

हॉकिन्स जॉन और फिलिप टर्नर, “मैनेजिंग फॉरान डेब्ट एण्ड लिक्विडिटी रिस्क इन इमर्जिंग इकानमिज़: एन आवरव्यू”, बीआईएस, 2000।

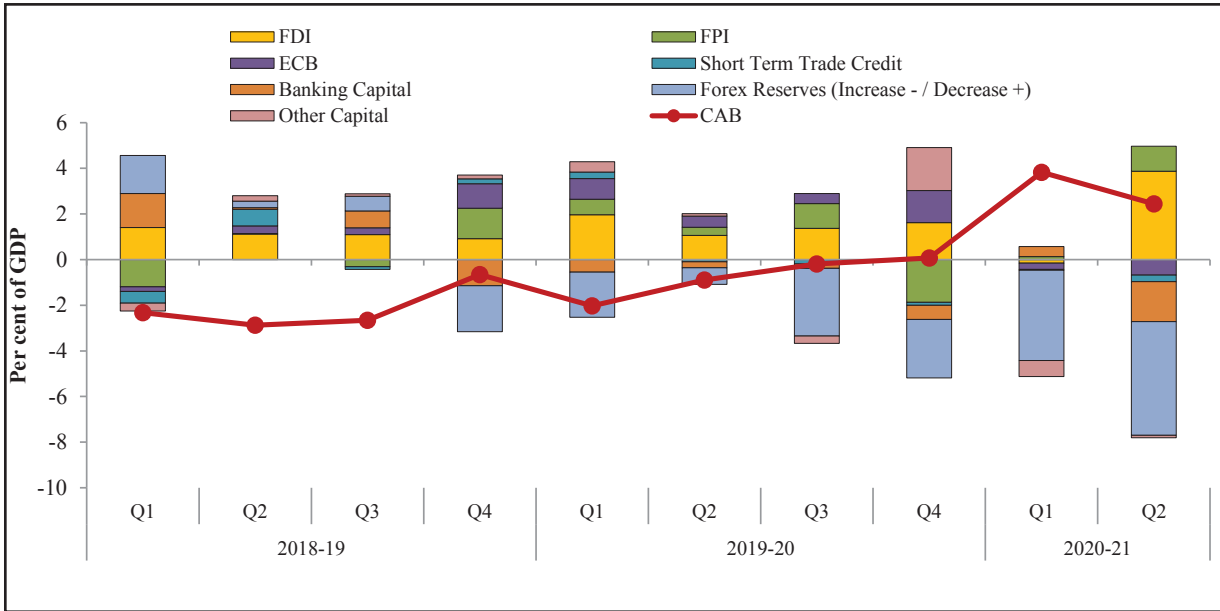
कॉर्डेला, टी., टिक्की, एल और रूइज़-अराज़ एम. “डेब्ट ओवरहेड ऑर डेब्ट इर्रेलेवेन्स? रिजिजिटिंग द डेब्ट ग्रोथ लिंक”, स्टाफ पेपर्स, वॉल्यूम 57, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी, 2010

कोहेन, डैनियल, “ग्रोथ एण्ड एक्सटर्नल डेब्ट: ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द अफ्रीकन एण्ड लैटिन अमेरिकन ट्रेजिडिज़”, सेन्टर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च डिस्कशन पेपर, नम्बर 1753, 1997

कुल भुगतान शेष

3.26 भारत, एक विकासशील और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था होने के नाते, आमतौर पर चालू खाते पर घाटे को चलाता है ताकि उच्च निवेश के लिए विदेशी बचत के साथ घरेलू बचत को पूरक बनाया जा सके। चालू खाता घाटा आमतौर पर एक पूंजी खाता अधिशेष द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के बाद से, भारत चालू खाता अधिशेष का अनुभव कर रहा है और मजबूत पूंजी प्रवाह के साथ भुगतान शेष की स्थिति की ओर बढ़ रहा है (चित्र 16)।

चित्र 16: भारत के भुगतान शेष के रूझान



स्रोत: आरबीआई

विवरण संलग्नक में उपलब्ध

भारतीय रुपया (₹) विनिमय दर

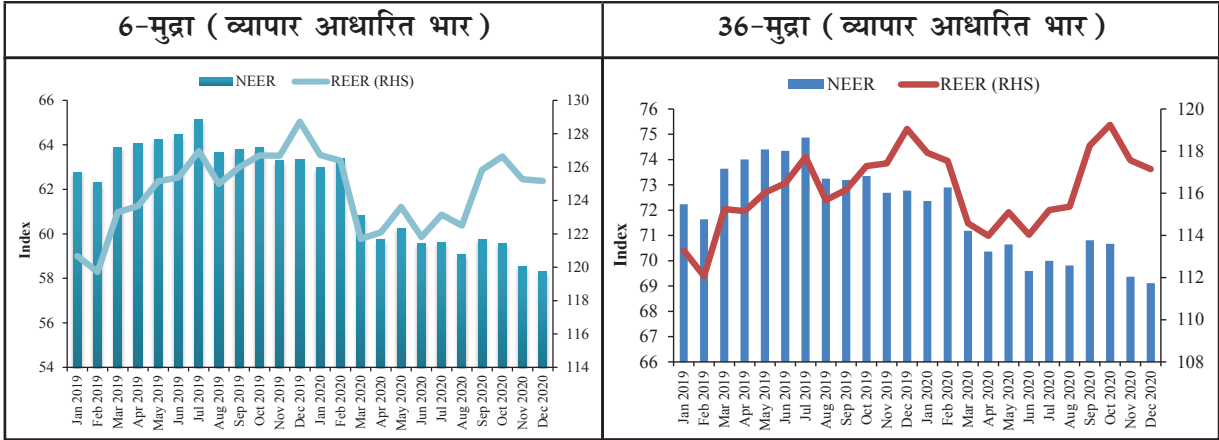
3.27 2019-20 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में 1.4 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ (वर्ष दर वर्ष आधार)। अक्टूबर 2019 अंत और मार्च 2020 अंत के मध्य रुपया 1.9 प्रतिशत मजबूत हुआ। हालांकि मलेशिया रिंगिट, थाई बाट, फिलीपाईन पिसो, चीनी युआन, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, मैक्सिकन पिसो, इंडोनेशियाई रुपैया जैसी उभरती बाजार मुद्राओं की तुलना में यह मजबूती सामान्य थी। हालांकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में यह मजबूत था, अक्टूबर 2019 अंत और मार्च 2020 अंत के मध्य यह अन्य मुख्य मुद्राओं की तुलना में कमजोर रहा। यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और येन के प्रति इसका मूल्यह्रास क्रमशः 4.5 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत रहा।

3.28 16 अप्रैल 2020 को अपने न्यूनतम स्तर 76.86 रुपये के स्तर पर मूल्यह्रास के बाद, घरेलू इक्विटी बाज़ार में एफ.पी.आई. प्रवाह और अमेरिकी डालर में कमजोरी के कारण, रुपये में पुनः सुधार हो गया। 36 मुद्रा NEER के संदर्भ में मार्च 2020 से दिसम्बर 2020 के बीच रुपये में 2.9 प्रतिशत का ह्रास हुआ हुई REER के संदर्भ में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

6-मुद्रा नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एन.ई.ई.आर.) (व्यापार आधारित भार) के संदर्भ में अक्टूबर 2020 से मार्च 2020 की अवधि में रुपया 2.0% तक ह्रासित हुआ और यह वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) के संदर्भ में 4.1 प्रतिशत सुधार है, हालांकि, आर.ई.ई.आर. के संदर्भ में इसमें 2.1% सुधार हुआ।

नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एन.ई.ई.आर.) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) 6-मुद्रा सूचकांक और

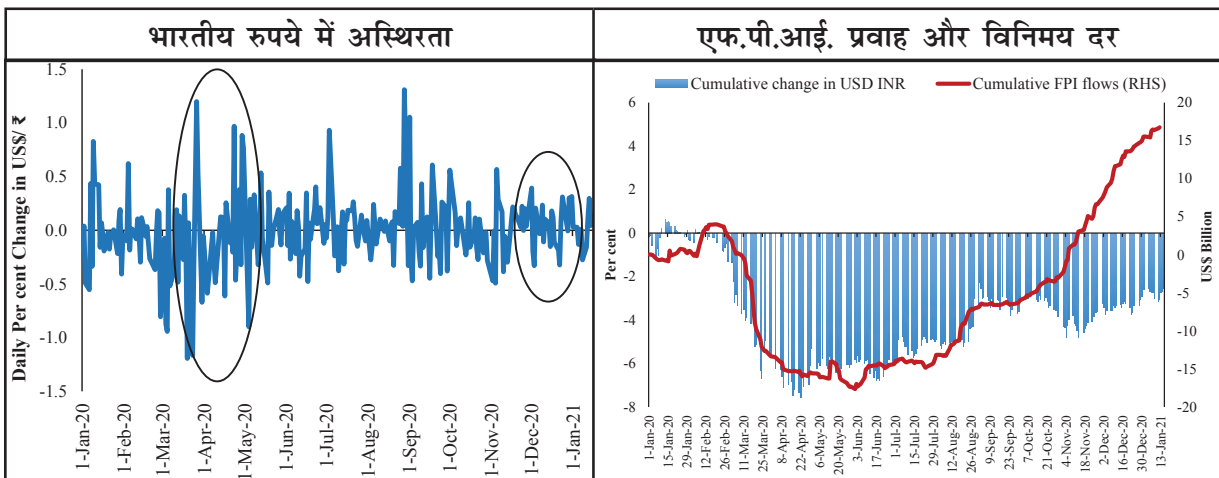
चित्र 17: 36-मुद्रा सूचकांक (व्यापार आधारित भार) (एन.ई.ई.आर. और आर.ई.ई.आर. का अलग अक्ष पर आलेख) सूचकांक आधार वर्ष 2004-05=100



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

3.29 रुपये के विनिमय दर पर RBI के नीति बाजार के ताकतों के द्वारा निर्धारण इसे किसी पूर्व-निर्धारित लक्ष्य स्तर अथवा बैंड के बिना, विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता से व्यवस्थित रूप से बाज़ार की स्थिति बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करने दी जाये। इस देशांतरगामी महामारी के कारण जनवरी-फरवरी 2020 में US \$1.42 बिलियन डालर प्रवाह के बाद मार्च 2020 में 15.92 अमेरिकी डालर प्रवाह हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई परंपरागत और अपरंपरागत साधन अपनाए जिससे वित्तीय बाज़ारों में वित्तीय स्थिरता और नियंत्रित स्थितियों को सुनिश्चित किया जा सके और यह रुपये की अस्थिरता (उतार-चढ़ाव) को नियंत्रित करने में बहुत हद तक सफल रहा है (चित्र 18 देखें)। उन्त अर्थव्यवस्थाओं में सेंट्रल बैंकों द्वारा दिए गए बड़े प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप भारत जैसे उभरते बाज़ारों में पूंजी प्रवाह बढ़ गया है, जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो गई है और स्थानीय मुद्रा भी मजबूत हो गई है। विदेशी मुद्रा बाज़ार में विवेकपूर्ण हस्तक्षेप रुपये में एकतरफा चढ़ाव को रोकने के लिए अपेक्षित हुआ है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया है (चित्र 18)

चित्र 18: विदेशी विनिमय बाज़ार में भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप का प्रभाव

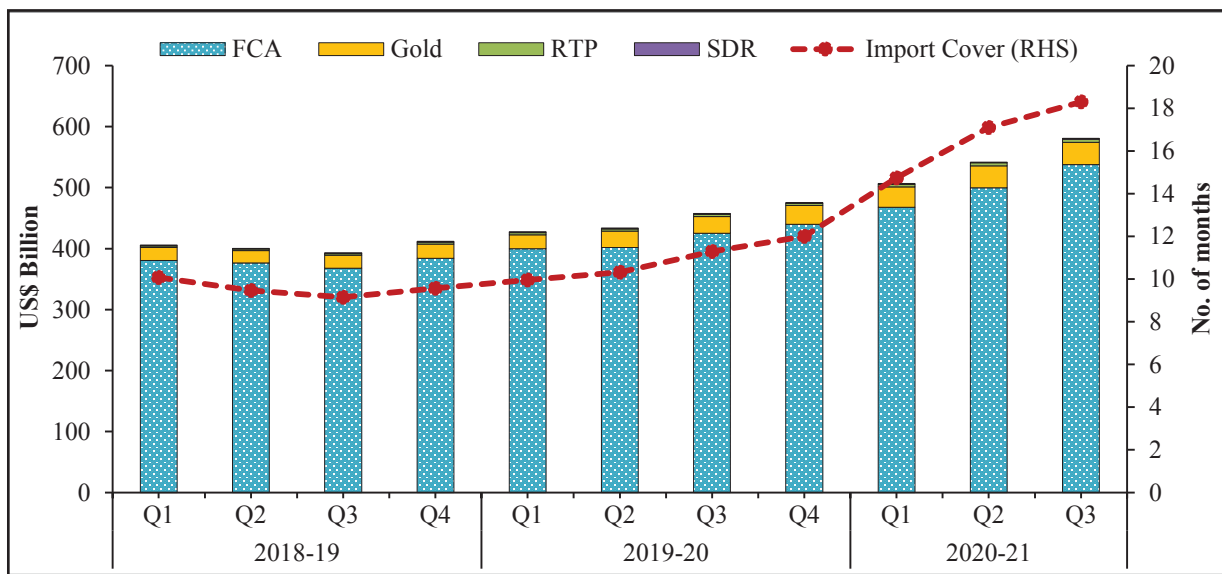


स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा भंडार

3.30 2020-21 की प्रथम छमाही में आरक्षित निधियों में सुधार के लिए चालू खाता बैलेंस में सुधार एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, मज़बूत पूंजी प्रवाह, विशेषकर अनुवर्ती माह में, एफ.डी.आई. और एफ.जी.आई. 18 दिसंबर, 2020 तक 586.1 बिलियन अमेरिकी डालर, विदेशी मुद्रा भंडार को उच्चतर स्तर पर ले गया और इसमें 16 माह तक के आयात को सम्मिलित कर लिया। सितंबर 2020 की समाप्ति तक चीन, जापान, स्विटजरलैंड और रूस के बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। मार्च 2020 की समाप्ति तक 229.7% की तुलना में सितंबर 2020 की समाप्ति तक भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय देयताएं विदेशी मुद्रा भंडार 210.7% है।

चित्र 19: विदेशी विनिमय आरक्षित निधियों और इम्पोर्ट कवर के स्रोत



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.)

नोट: ऊपर सूचित की गई विदेशी विनिमय आरक्षित निधियां तिमाही/माह की अंतिम की तारीख की हैं।

3.31 मौद्रिक नीति की अपरिहार्य उलझनों के बिना जहां तक मुद्रास्फीति सुसाध्य थी वहां इस विदेशी विनिमय आरक्षित निधि की अभिवृद्धि ने देशी चल-निधि के सहगामी निर्गमन को अपरिहार्य बना दिया और यह बड़े पैमाने के सरकारी-ऋण में सहायक बना। हालांकि जब मुद्रास्फीति 4+/-2% के मौद्रिक नीति-स्तर के ऊपर चले जाने के कारण सुर्खियों में आई तब भारतीय रिज़र्व बैंक को मुंडेल-फ्लेमिंग त्रिलम्मा अथवा इंपॉसिबल ट्रिनिटी समस्या जोकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की चिरसम्मत समस्या है, का सामना करना पड़ा कि क्या-वह ओपन कैपिटल अकाउंट को बनाए रखे या-अपनी विनिमय दर को स्थिर करे या-अभी भी स्वतंत्र मुद्रा नीति को अपनाए रखे। भुगतान संतुलन के एक बड़े अधिशेष का सामना करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक को दो विकल्पों का सामना करना पड़ा है: या तो अधिशेष को अवशोषित कर ले और अधिक विदेशी विनिमय आरक्षित निधि को जमा कर ले या रुपए की मूल्यवृद्धि होने दे। मुख्यतया आपूर्ति भंग के कारण हुई मुद्रास्फीति और इसमें स्थिरता आने की आशा को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करने, निधियों का संचय करने, रुपए की एकतरफा मूल्य वृद्धि को रोकने और विस्तार वादी मौद्रिक नीति को बढ़ावा देने का चयन किया। तथापि सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति के बढ़े हुए स्तर की पुष्टि के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक को एक ओर मौद्रिक नीति को कठोर बनाना जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और दूसरी ओर विकास को प्रोत्साहित करना।

3.32 भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी विनिमय आरक्षित निधियों (मुद्रा भंडार) में वृद्धि मोटे तौर पर चालू खाते के अधिशेष के कारण हुई है, जिसका आधार, निर्यात की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के स्थान पर आयात में होने वाला संकुचन है। चालू खाता अधिशेष, अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि में, राष्ट्रीय बचत-निवेश संतुलन का पर्याय है। चालू खाता अधिशेष का तात्पर्य निवेश के सापेक्ष उच्च स्तर की राष्ट्रीय बचत से है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अन्य देशों के बांडों/प्रतिभूतियों में निवेश को भी निरूपित करती है, वस्तुतः विदेशों में निवेश करने को। भारत जैसे विकासशील देश को अपनी वृद्धि को बढ़ाने के लिए घरेलू निवेश पर खर्च करने की आवश्यकता है, जिसे विदेशी बचत द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है। इसलिए, वित्त वर्ष 2021-22 निवेश पर में इस अधिशेष का खर्च निवेश पर पर्याप्त रूप से किया जा सकता है।

3.33 एक स्वस्थ विदेशी क्षेत्र के संतुलन का स्थायी उपाय निर्यात के माध्यम से उपार्जन को बढ़ाना है जिससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए, व्यापार को सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें व्यापार की लेन-देन और समय संबंधी लागत को कम करके, भारतीय निर्यात को अधिक स्पर्धात्मक बनाया जाता है।

निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का अभिक्रम

3.34 भारत स्वीकार करता है कि आज की परस्पर संबद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था में, व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, तेज और समन्वित करने के प्रयास व्यापार के विस्तार को बढ़ावा देंगे और विश्व-स्तरीय उत्पादन प्रणाली के द्वारा उत्पादन करने में सहायक होंगे। विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, अर्थात् 31 मार्च, 2021 तक जिससे वर्तमान योजनाएं सतत् रूप से जारी रहें।

व्यापार की सुविधा

3.35 अक्षम और अत्यधिक बोझिल नियामक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण व्यापार रोधों को कम करने के उद्देश्य से, विश्व-व्यापार संगठन की बैठक में व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) हुए, और इनको 22 'फरवरी 2017 से लागू किया गया। तदनुसार, भारत में राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ), अगस्त 2016 में गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव थे। इसमें वर्ष 2017-2020 की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) को तैयार किया गया था जिसमें वे विशिष्ट गतिविधियां सम्मिलित थीं जिससे व्यापार की अतिरिक्त बाधाओं को दूर किया जा सकता था। वर्ष 2020 से 2023 की अवधि के लिए, एक नई राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) को तैयार किया जा रहा है, जिससे अतिरिक्त सुधारों को लाया जाए और व्यापार सुविधा प्रयासों को सहारा दिया जाए तथा दक्ष, पारदर्शी, जोखिम आधारित, समन्वित, डिजिटल, परिपूर्ण व प्रौद्योगिकी संचारित प्रक्रियाओं के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर क्लियरेंस इकोसिस्टम को बदला जा सके।

3.36 भारत एनसीटीएफ के मार्गदर्शन में टीएफए कार्यान्वयन में पहले से ही बड़े प्रयास कर रहा है। कई प्रतिबद्धताओं जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना (अनुच्छेद 10.4), माल की निकासी के लिए जोखिम प्रबंधन (अनुच्छेद 7.4) आदि को, जो कि नियत वर्ष 2022 तक नहीं तो अनिवार्य हो जाते, पहले ही कार्यान्वित कर विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता अधिसूचना जिनमें आयात निर्यात प्रक्रियाओं, (इनक्वारी प्वाइंटों) पूछताछ स्थानों, सिंगल विंडो आदि से संबंधित सूचना सम्मिलित है, को अप्रैल 2019 में अधिसूचित कर दिया गया है जिससे पारदर्शिता और खुलेपन पर आधारित भारत का व्यापार को सुविधाजनक बनाए जाने का संकल्प निरूपित होता है। इसके आगे कोविड-19 के दौरान व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न विनियामक उपाय किए गए और छूट को बढ़ाया गया, जिसमें 24x7 क्लियरेंस, समर्पित सिंगलविंडो, आयात घोषणाओं में विलंब के लिए क्षमादान, देर से दाखिल शुल्क जमा करने की छूट,

बांड के बजाय वचन पत्र आदि शामिल हैं। व्यापार में भावी निर्णायक स्थिति प्राप्त करने और ट्रेड ऑटोमेशन के लक्ष्य के लिए उठाए जाने वाले कदमों में भारत सबसे आगे रहा है, और सतत रूप से इस दिशा में सुधार कर रहा है, जिसका उल्लेख यूनाइटेड नेशन के डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड पर किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में मिलता है।

निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट

3.37 भारत की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं जिसमें मर्चेडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) शामिल है, को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2018 के शुरुआत में विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी गई थी। डब्ल्यूटीओ पैनल की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया है कि MEIS एक “निषिद्ध-सब्सिडी” है और इसे वापस ले लेना चाहिए, भारत सरकार ने इसके खिलाफ अपील दायर की है। उद्योग का समर्थन जारी रखने और निर्यात समुदाय के बीच किसी भी अनिश्चितता को खत्म करने के लिए, सरकार ने सभी निर्यात वस्तुओं के लिए 1 जनवरी 2021 से प्रभावी विश्व व्यापार संगठन के नियमों का अनुपालन करने वाली एक नई योजना, जिसका नाम निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट है, आरंभ कर दी है।

3.38 इस योजना के अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए जाने वाले शुल्क और करों जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, परिवहन के लिए उपयोग किए गए ईंधन पर लगने वाला मूल्य वर्धित कर जिनके लिए किसी अन्य वर्तमान प्रणाली के अधीन न तो छूट दी जाती है अथवा न ही धन की वापसी होती है, उन से संबंधित राशि को निर्यातकों के सीमा-शुल्क के बही खाते में वापस कर दिया जाएगा। क्रेडिट का उपयोग आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है या इसे अन्य आयातकों को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिससे निर्यात के लिए लेनदेन में आसानी होती है। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट की दरों को वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

3.39 घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, 1.46 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन-से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। पीएलआई योजना के तहत दस-पहचाने गए चैंपियन क्षेत्र इस प्रकार हैं—एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी (पांच साल की अवधि के लिए स्वीकृत वित्तीय परिव्यय 18,100 करोड़

रुपये), इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद (रुपये 5,000 करोड़ रुपये), ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स (57042 करोड़ रुपये), फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स (15,000 करोड़ रुपये), दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद (12,195 करोड़ रुपये) कपड़ा उत्पाद (10,683 करोड़ रुपये), खाद्य उत्पाद (10,900 करोड़ रुपये), उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल (4,500 करोड़ रुपये), घरेलू-वस्तुएं (एसी और एलईडी) (6,238 करोड़ रु.) और स्पेशलिटी स्टील (6,322 करोड़ रु.)। ये मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (40,951 करोड़ रु.), क्रिटिकल की-स्टार्टिंग मैटीरिअल/ड्रग इंटर-मीडियारिज़ और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रीडीएन्ट (6,940 करोड़ रु.) और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण (7420 करोड़ रु.) के लिए पहले से अधिसूचित पीएलआई योजनाओं से अतिरिक्त हैं।

3.40 इस योजना से विश्व स्तर पर भारतीय निर्माता को इन दस क्षेत्रों में प्रतियोगी बनाने की उम्मीद जागेगी, मूल-योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित होगा; दक्षता सुनिश्चित होगी; बड़े पैमाने की क्वायतें होंगी; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उत्पादन-पूर्व सुविधाएं मिलेंगी; निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। यह योजना वैश्विक पूंजी-बहुल कंपनियों

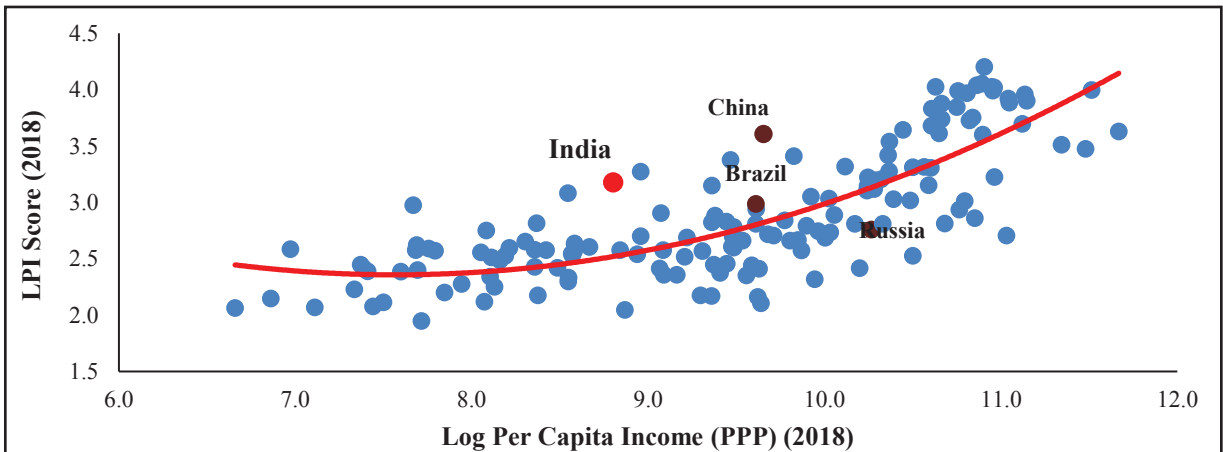
के भारत में उत्पादन आरंभ करने के लिए भी उत्प्रेरित करती है। उत्पादन में विकास और औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात से भारतीय उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा और विचारों का अनुभव प्राप्त होगा जिससे उसकी क्षमताओं में और अधिक नवोन्मेष लाकर सुधार करने में सहायता मिलेगी। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा और विनिर्माण संबंधी नियमों के अनुकूल बनाए जाने से न केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ने में सहायता मिलेगी अपितु देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र को उत्पादन पूर्व सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इससे अर्थव्यवस्था का व्यापक विकास होगा और रोजगार के विशाल अवसर उत्पन्न होंगे।

व्यापार संबंधित संभार-तंत्र

3.41 कोविड-19 (लॉजिस्टिक) महामारी ने एक मजबूत संभार-तंत्र क्षेत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया है इसका उपयोग आपातकाल और आपूर्ति श्रृंखला भंग की परिस्थिति में किया जा सकता है। कुछ संरचनात्मक कमजोरियों जैसे कि अत्यंत खंडित स्वामित्व का होना, कुछ ही बड़े व्यापारियों की उपस्थिति, व्यापार सक्रियताओं के समेकन में कमी, अन्य माल वाहकों/साधनों का इष्टतम स्तर से कम उपयोग किया जाना और सड़क के माध्यम से ही अधिकांश माल/वस्तुओं का परिवहन किया जाना, यूजर सेक्टर (अनेक मंत्रालय और एजेंसियां) द्वारा संपूर्ण रूप से क्षेत्र विशेष के कौशल तथा कंप्यूटर-शिक्षा को व्यावहारिकता में नहीं लाया जाना, संगत नीतियां और विनियम का नहीं होना आदि, इन सभी के बावजूद भारत में व्यापार संबंधी संभार-तंत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

3.42 सीमा-पार के व्यापार संबंधी पैरामीटरों को सुधारने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2018 के 146वें स्थान से सुधर कर वर्ष 2020 में 68वें स्थान पर पहुंच गया है। यह पैरामीटर माल के निर्यात और आयात की संभार-तंत्र आधारित प्रक्रिया से जुड़े समय और लागत का आकलन करता है। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मंस से जुड़े समय और लागत का आकलन करता है। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मंस इंडेक्स (एलपीआई) देशों के संभार-तंत्र की सापेक्ष दक्षता का आकलन करता है। इस सूचकांक में, 160 देशों में वर्ष 2014 के 54वें स्थान की तुलना में भारत वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर था। वर्ष 2018 में एलपीआई द्वारा किए गए 24 देशों के विश्लेषण में भारत दस लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वाले 9 देशों में से है और इसका स्कोर 3 से अधिक है। विकास स्तर को नियंत्रित करने के बाद भारत का निष्पादन औसत से अधिक रहा है और यह उसके ब्रिक्स समूह के सहयोगी देशों में से कुछ से अच्छा है (चित्र 20)।

चित्र 20: विकास स्तर के लिए एलपीआई स्कोर को नियंत्रित करना



स्रोत: विश्व बैंक डेटासेट पर आधारित

3.43 राष्ट्रीय संभार तंत्र प्रणाली ऐसे चरण में है जिसका अनावरण निकट भविष्य में किया जाना है जिसमें एक ऐसे आधुनिक, दक्ष और समुत्थानशील संभार-तंत्र को विकसित करने का दृष्टिकोण समाहित किया गया है, जिससे डायनामिक लॉजिस्टिक प्रोसेस, प्रौद्योगिकी और प्रौफेशनल इस क्षेत्र का आधार बन सकेंगे और यह सभी परिवहन के विभिन्न माध्यमों और स्टॉक(मॉल)-प्रबंधन से निर्बाध रूप से जुड़ सकेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि अधिक विश्वसनीय, किफायती, पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित और साम्यिक सुविधाओं को देने वाला संभार-तंत्र सभी को मिल सकेगा।

3.44 प्रक्रिया संबंधी कुछ ऐसे सुधार जिनसे संभार-तंत्र में सुधार होने लगा है, इस प्रकार हैं- जीएसटी के कारण अंतर-राज्य सीमा पार जाने के लिए प्रतीक्षा समय को घटाया गया है, वहन क्षमता को बेहतर बनाए जाने के लिए भारी वाहनों के लिए एक्सएल-भार-नियम में संशोधन किया गया है, ई-संचित के माध्यम से कागज रहित आयात-निर्यात व्यापार प्रक्रिया का आरंभ किया गया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा तुरंत सीमा शुल्क के माध्यम से फेसलेस मूल्यांकन किया जाने लगा है, मुख्य पत्तनों पर स्कैनरों का अधिष्ठापन किया गया है, सभी महत्वपूर्ण पत्तनों पर पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम का कार्यान्वयन किया गया है, सभी आयात-निर्यात कंटेनरों की मार्ग में पहचान करने और खोज करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) का लेबल लगाया जा रहा है, टोल प्लाजा आदि पर समय की हानि को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम फ़ास्ट-टैग को अनिवार्य किया गया है।

3.45 कुछ आधारभूत संबंधित पहले जो क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं, वे निम्न प्रकार हैं:-

- क) *भारतमाला परियोजना* राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया अम्ब्रेला-कार्यक्रम है जिसमें लगभग 107 बिलियन डॉलर के निवेश के द्वारा 80,000 किमी से अधिक की सड़कों, राजमार्गों, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- ख) *सागरमाला कार्यक्रम* का लक्ष्य पत्तन आधुनिकीकरण और नए पत्तनों का विकास, पत्तन संयोजकता संवर्धन, पत्तन संबंधी औद्योगिकीकरण, तटीय-समुदाय विकास (कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट) और तटीय-पोत परिवहन (कोस्टल शिपिंग) को प्रोत्साहन देना है। 508 परियोजनाओं की पहचान की गई है और 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है।
- ग) *मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क-संचलन* के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो माल एकत्र करने, वितरण और बहुल माध्यम परिवहन को सक्षम बनाएगा। इनके द्वारा आधुनिक यंत्रचालित मालगोदाम क्षेत्र उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ बॉन्डेड स्टोरेज यार्ड में रखे हुए माल की सीमा-शुल्क-निकासी, मालगोदाम प्रबंधन सेवाओं (वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज) जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।
- घ) *समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी)* का उद्देश्य परिवहन के प्रति यूनिट खर्च में बचत करना है जिसमें मालगाड़ियों की गति को बढ़ाया जाएगा और रेल-वैगन की दो क्रमिक लोडिंग के बीच समय के अंतराल को कम किया जाएगा। लगभग 70 प्रतिशत माल की डीएफसी में स्थानांतरित होने की उम्मीद की जा रही है, जिससे भारतीय रेल की क्षमता का उपयोग अन्यत्र किया जा सकेगा।
- ङ) *एक्सपोर्ट स्कीम के लिए ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर (टीआईईएस)* का उद्देश्य राज्यों से निर्यात की वृद्धि के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचे के निर्माण में सहायता करना है।

3.46 कुछ डिजिटल/तकनीकी पहल जिनका विकास किया जा रहा है।

- क) लॉजिस्टिक्स प्लानिंग एंड परफॉरमेंस मॉनिटरिंग टूल (एलपीपीटी) विभिन्न संभार-तंत्र आधार भूत संरचनाएं जैसे, पत्तन, विमानपत्तन, राष्ट्रीय और राजमार्गों से जुड़े विभिन्न कॉरिडोर, इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी, इत्यादि) के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन और आस्तियों के उपयोग का समसामयिक मोनीटरन करता है।
- ख) भारत लॉजिस्टिक प्लेटफार्म (आईएलओजी)-सरकार द्वारा वर्षों से अनेक सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग किया जा रहा है जैसे कि भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई गेटवे (आईसीईगेट) और व्यापार सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड (एसडब्ल्यूआईएफटी); समुद्रपत्तनों में कार्गो हैंडलिंग के लिए पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस); भारतीय रेल द्वारा माल संचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा “वाहन” (राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण प्रणाली)। हालांकि, प्रत्येक प्रणाली के स्वामी ने महत्वपूर्ण अंतरालों को छोड़ते हुए।
- ग) घटक प्रणालियां जिनका विकास भारतीय लॉजिस्टिक प्लेटफार्म के साथ-साथ किया जा रहा है और जिनको सार्वजनिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से भारतीय लॉजिस्टिक प्लेटफार्म के साथ जोड़ दिया जाएगा वे इस प्रकार हैं-सिक्योरिटी लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज (आधार एंड ब्लॉकचेन बेस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल); ट्रक विजिबिलिटी एंड पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म (ई-बिल तथा वाहन के साथ एकीकृत); नेशनल ई-रजिस्टर ऑफ वेयरहाउसिंग; डिजिटल ट्रेकिंग; लॉजिस्टिक अकाउंट नंबर (एलएएन); डिजिटल ग्रीन कॉरिडोर; डिजिटल पोर्ट डीकॉनजेशन एंड कंटेनर ट्रेकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम।

3.47 यह अनुमान किया जा रहा है कि संभार-तंत्र क्षेत्र में 12 मिलियन कामगारों को रोजगार मिलेगा जिसमें मुख्यता भू-परिवहन, मालगोदाम (भंडारण और पैकेजिंग) आपूर्ति श्रृंखला और कोरियर व तत्काल कोरियर सेवाएं सम्मिलित होंगी। उन्हें समुचित कौशल प्रदान करने के लिए, स्कूल स्तर पर कक्षा 9 और 10 के लिए लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला पर पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीआई), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और राज्य कौशल मिशन के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक में शुरू किया जाएगा।

भारत का विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ संबंध

3.48 विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य भारत है, जिसने प्रमुख व्यापार नीतियों के प्रभावी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संरक्षणवाद में वृद्धि, विवाद समाधान के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्यों की अपर्याप्तता, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) आदि की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरूप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों ने इसकी प्रभावकारिता पर सवाल उठाया है क्योंकि यह संस्था मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। डब्ल्यूटीओ सुधार पर चल रही चर्चाओं में भारत का प्रस्ताव विकास और समावेशी विकास के महत्व की पुनः पुष्टि करता है। भारत के प्रस्ताव के व्यापक तत्वों में शामिल हैं :

(i) बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मुख्य मूल्यों का संरक्षण; (ii) विवाद निपटान प्रणाली में गतिरोध का समाधान करना; (iii) विकास संबंधी विषयों की सुरक्षा करना; और (iv) पारदर्शिता और अधिसूचनाएं।

3.49 15-16 अक्टूबर, 2020 को आयोजित डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स काउंसिल की बैठक के दौरान भारत और दक्षिण अफ्रीका ने सीमित समय अवधि के लिए कोविड-19 के उपचार और नियंत्रण, रोकथाम के लिए टीआरआईपीएस समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट देने का प्रस्ताव दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बौद्धिक संपदा अधिकार कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके एवं चिकित्सा उत्पादों में शामिल टीके और चिकित्सा विधान को आसानी से प्राप्त करने में अवरोधक न बने। इस प्रस्ताव को व्यापक रूप से कई डब्ल्यूटीओ सदस्य, सिविल सोसाइटी और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन प्राप्त हुआ है।

3.50 डब्ल्यू टी ओ की अपीलीय निकाय (एबी) एक स्थायी निकाय है जिसका उद्देश्य विवाद निपटान समाधान (डीएसयू) द्वारा निधि से सम्बन्धित मामलों का निपटान करना है। यह सात सदस्यों से बनी चार वर्ष की अवधि के लिए होती है तथा इन सात सदस्यों की सिर्फ एक बार पुनर्नियुक्ति होने की संभावना रहती है। जुलाई, 2017 से संयुक्त राज्य ने ए बी नियुक्तियों को इसलिए रोक कर रखा है क्योंकि यह डी एस यू मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है जो 'अपीलीय संस्था में व्याप्त संकट' को दर्शाता है। 10 दिसम्बर, 2019 से अपील की सुनवाई हेतु तीन सदस्यों से भी कम सदस्यों के रह जाने पर, ए बी, डी एस यू के मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है। इस संकट के परिणामस्वरूप 23 डब्ल्यू टी ओ सदस्यों ने मल्टीपार्टी अंतरिम मध्यस्थता तंत्र का गठन किया है जो एबी के अन्तर्गत अपीलीय समीक्षा के प्रक्रियागत एवं महत्वपूर्ण पहलू को समीप से दर्शाता है। एम पी आई ए के मुख्य सदस्यों में चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैन्ड है। अभी तक भारत एम पी आई ए का सदस्य नहीं बना है। भारत दो चरणों के बाध्यकारी डब्ल्यू टी ओ विवाद निपटान तंत्र के सामान्य कामकाज की बहाली और संरक्षण का समर्थन करता है।

3.51 कृषि के क्षेत्र में, भारत के साथ अन्य विकासशील देश खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक स्टॉकधारी के विषय पर स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। यह महामारी के समय और भी प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि सरकार को जनता की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक खाद्यान्न कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न के संचितरण को आगे बढ़ाना पड़ा। भारत कृषि पर मौजूदा समझौते (ए आए) में असंतुलन और विषमता और विकासशील देशों पर पड़ते उनके प्रभाव का मुद्दा भी उठा रहा है। दिसम्बर 2017 के ब्युनस आयर्स मंत्रिस्तरीय निर्णय (एम सी 11) के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के सदस्य वर्ष 2020 में अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एम सी 12) द्वारा मत्स्य सप्लाइ पर संगठन बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। डब्ल्यू टी ओ में नियमों पर चल रही है और ये मासिक कलस्टर के रूप में संचालित की जा रही है।

3.52 विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने 1998 में इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क लगाने पर सहमति नहीं दी और तब से मंत्रिस्तरीय बैठकों में समय-समय पर मोरोटोरियम (स्थगन) बढ़ा दिया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ई-कॉमर्स पर वर्क प्रोग्राम के तहत मार्च 2020 में - 'द ई-कॉमर्स मोरोटोरियम: कार्य और इसके प्रभाव' को संयुक्त रूप में प्रस्तुत किया, जो अन्य बातों के साथ यह तर्क देता है कि विकासशील देशों के लिए अपनी डिजिटल उन्नति के लिए अधिस्थगन पर पुनर्विचार करना महत्वपूर्ण है। ई-कॉमर्स में नियम

बनाने के लिए बहुपक्षीय जनादेश प्राप्त करने में विफलता के जवाब में, जनवरी, 2019 में, ई-कॉमर्स पर एक संयुक्त बयान डब्ल्यू टी ओ के नियम बनाने वाले छिहत्तर (76) सदस्यों की ओर से जारी किया गया था। भारत उक्त बहुपक्षीय पहल में शामिल नहीं हुआ है। भारत का मानना है कि विकासशील देशों को घरेलू भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, सहायक नीति और विनियामक ढांचे को बनाने और डिजिटल विभाजन को पार करने, डिजिटलीकरण के साझा लाभों तथा डिजिटल क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

3.53 भारत के घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के आधार पर तथा माल के डंपिंग/सब्सिडी देना, घरेलू उद्योग को हुई हानि, डंपिंग/सब्सिडी और घरेलू उद्योग को हुई हानि के मध्य अनौपचारिक लिंक के प्रथम दृष्टि पर अधारित साक्ष्य के आधार पर एंटी डंपिंग, एंटी सब्सिडी की सुरक्षा जांच करेगा। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने एक ऑनलाइन पोर्टल पेश किया है- ए आर टी आई एस (भारतीय उद्योग और अन्य हितधारकों के लिए व्यापार में उपचार के लिए आवेदन) जिसने एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे विभिन्न व्यापार उपचारों हेतु ऑनलाइन याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। 1.4.2020 से 30.10.2020 की अवधि के आधार पर डी जी टी आर ने 43 एंटी डंपिंग जांच, 4 काउंटरवेलिंग जांच और सेफगार्ड जांच शुरू की है।

भावी परिदृश्य

3.54 कोविड-19 महामारी ने विभिन्न देशों कि विकसित अर्थव्यवस्थाएँ के लिए अलग-अलग बाहरी क्षेत्रों उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ को प्रभावित किया है। हांलांकि निर्यात और आयात में संकुचन के कारण ए ई को बड़े संकुचन और ई एम डी ई को कम संकुचन का सामना करना पड़ा। भारत में, लॉकडाउन प्रतिबंधों की कैलिब्रेटेड सहजता ने निर्यात और आयात दोनों में संकुचन को कम कर दिया और आयात में तेजी के साथ सुधार हुआ, जिससे वर्तमान वर्ष की तिमाही में व्यापारिक व्यापार घाटे के प्रगतिशील विस्तार को बढ़ावा मिला। भारत के व्यापारिक व्यापार में सुधार की प्रवृत्ति इक्विटी कैपिटल प्रवाह मजबूत एफडीआई प्रवाह और विदेशी मुद्रा भंडार के निरंतर निर्मित होने से आगे बढ़ी है। सुविधाजनक विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़े हुए घरेलू निवेश के लिए बहुत जरूरी है। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक उत्पादन मूल्य श्रृंखलाओं का विघटन भारत के लिए श्रृंखला के प्रमुख नोडस में से एक बनाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। उपरोक्त के रूप में प्रलेखित विभिन्न निर्यात पहलुओं और आर बी आई एवं सरकार द्वारा लिए गए कदम से भारत में सतत निर्यात प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त होगा।

अध्याय एक नजर में

- कोविड 19 महामारी के कारण वैश्विक व्यापार में पतन, कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और बाहरी वित्तीय परिस्थितियों में तंगी के साथ चालू खाता शेष एवं विभिन्न देशों की मुद्राओं में कई प्रकार के दुष्प्रभाव हुए।
- आयात के धीमा होने से चीन और यूएस के मध्य व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है।
- हांलांकि रत्न और गहने, इंजीनियरिंग के सामान, कपड़ा और संबद्ध उत्पादों का निर्यात कम हुआ है। दवाओं और फार्मा, सॉफ्टवेयर और कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में सुधार हुआ। विशेष रूप से फार्मा निर्यात “विश्व की फॉर्मेसी” बनने की क्षमता रखता है।

- कुल मिलाकर 17 वर्षों के अंतराल के बाद, चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत को चालू खाता अधिशेष की उम्मीद है।
- 8 जनवरी, 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 बिलियन यू एस डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- पूंजी खाते का शेष मजबूत एफडीआई और एफपीआई प्रवाह से मजबूत रही।
- विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप ने वित्तीय स्थिरता एवं व्यवस्थित स्थिति को सुनिश्चित किया और साथ ही रुपये के एकतरफा अधिमूल्यन को भी बहुत हद तक नियंत्रित किया।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न कदमों में शामिल उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल पहल, बाहरी क्षेत्र को मजबूत करने और विशेष रूप से निर्यात करने में अत्यधिक सहायक होंगे।

अनुलग्नक 1: भुगतान शेष की राशि

		(यूएस डॉलर बिलियन में)									
		2018-19				2019-20				2020-21(पी)	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	माल का निर्यात (कस्टम के आधार) (1क+1ख)	82.1	81.4	80.6	86.0	80.9	78.3	79.1	75.1	51.4	74.2
1क	पीओएल निर्यात	11.8	11.8	13.0	9.9	11.1	10.1	10.9	9.1	4.9	7.3
1ख	गैर-पीओएल निर्यात	70.2	69.6	67.6	76.1	69.8	68.1	68.2	65.9	46.5	66.9
2	माल का आयात (कस्टम के आधार) (2क+2ख)	128.7	132.9	130.7	121.8	130.1	118.0	116.1	110.5	61.3	90.6
2क	पीओएल आयात	34.8	35.3	38.4	32.4	35.4	29.8	31.5	33.8	13.2	18.8
2ख	गैर-पोल आयात (2ख (i)+2ख (ii))	93.9	97.7	92.3	89.3	94.7	88.1	84.6	76.7	48.1	71.8
2ख(i)	सोना और चांदी आयात	9.7	9.8	8.3	8.8	12.5	5.3	7.5	5.6	1.3	6.2
2ख(ii)	गैर-पीओएल, गैर सोना और चांदी	84.2	87.9	84.0	80.5	82.2	82.8	77.0	71.1	46.8	65.5
3	व्यापार संतुलन (कस्टम आधार) (1-2)	-46.6	-51.5	-50.1	-35.8	-49.2	-39.7	-37.0	-35.4	-9.8	-16.4
4	मर्केनडाइज व्यापार संतुलन (बीओपी आधार)	-45.8	-50.0	-49.3	-35.2	-46.2	-38.1	-34.6	-35.0	-10.8	-14.8
5	अदृश्य (निवल (6+7+8))	29.9	31.0	31.5	30.6	31.8	31.8	33.2	35.6	30.0	30.3
6	सेवा (निवल)	18.7	20.3	21.7	21.3	20.0	20.4	21.9	22.0	20.5	21.2
7	अन्तरण (निवल)	17.0	19.3	17.4	16.2	18.0	20.0	18.7	18.4	17.0	18.4
8	आय (निवल)	-5.8	-8.6	-7.6	-6.9	-6.1	-8.6	-7.4	-4.8	-7.5	-9.3
9	चालू खाता (निवल) (4+5)	-15.8	-19.1	-17.8	-4.6	-14.3	-6.3	-1.4	0.6	19.2	15.5
10	विदेशी निवेश (निवल) (11+12)	1.4	7.6	5.2	15.9	18.7	9.9	17.8	-1.8	-0.2	31.6
11	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (निवल)	9.6	7.4	7.3	6.4	13.9	7.4	10.0	12.0	-0.8	24.6
12	एफ पी आई (निवल)	-8.1	0.2	-2.1	9.4	4.8	2.5	8.1	-13.7	0.6	7.0
13	विदेशी सहायता (निवल)	0.5	0.0	1.7	1.3	1.5	0.4	1.3	0.6	4.1	1.9
14	वाणिज्यिक उधार (एमटी और एलटी) (निवल)	-1.3	2.2	2.0	7.5	6.4	3.4	3.2	10.3	-1.4	-4.3
15	बैंकिंग पूंजी (निवल)	10.1	0.5	4.9	-8.1	-3.9	-1.8	-2.3	-4.6	2.2	-11.2
16	रुपया ऋण सेवा (निवल)	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
17	अल्पावधि ऋण (निवल)	-3.5	4.8	-0.7	1.5	2.0	-0.6	-1.4	-1.0	-0.2	-1.8
18	अन्य पूंजी (निवल)	-2.4	1.5	0.7	1.2	3.2	0.8	3.7	13.8	-3.5	-0.7
19	पूंजी खाता (निवल) (10+13+14+15+16+17+18)	4.8	16.6	13.8	19.2	27.9	12.1	22.4	17.4	1.0	15.4
20	त्रुटी और चूक (निवल)	-0.3	0.6	-0.3	-0.4	0.4	-0.7	0.7	0.9	-0.4	0.6
21	समग्र संतुलन (निवल) (9+19+20)	-11.3	-1.9	-4.3	14.2	14.0	5.1	21.6	18.8	19.8	31.6
22	विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि/कमी (गिरावट)+) (निवल)	11.3	1.9	4.3	-14.2	-14.0	-5.1	-21.6	-18.8	-19.8	-31.6

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और डी जी सी आइ एण्ड एस

नोट : पी: अनतिम